- 19th Year
- Issue: 204
- 27.11.2025 (THURSDAY)
- ROURKELA
- R.N.I. No. ORIHIN/2006/18978
- (Pages-6)
- Price:2.00

दैनिक
कलिंग समाचार
The kalingasamachar

e-paper-www.thekalingasamachar.com

प्रकाशक एवं संपादक : प्रकाश कुमार धल

Published From ODISHA, JHARKHAND & CHHATTISHGARH

संविधान है देश की आत्मा, कॉलोनियल सोच को त्यागें-राष्ट्रपति मुर्मू का 75वें संविधान दिवस पर बड़ा संदेश

२६/११ (संवाददाता): प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में 75वें संविधान दिवस के मौके पर संविधान दिवस प्रोग्राम के दौरान नौ भाषाओं -- मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, ओडिया और असमिया -- में भारत के संविधान का डिजिटल वर्शन जारी किया। प्रोग्राम के दौरान एक यादगार बुकलेट भारत के संविधान में कला और कैलिग्राफी भी जारी की गई। वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा स्थ्क्क मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा स्थ्क्क राहुल गांधी और दूसरे नेता संविधान दिवस इवेंट में शामिल हुए। पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग, जिसे अब संविधान सदन% कहा जाता है, के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस इवेंट को एड्रेस करते हुए प्रेसिडेंट मुर्मू ने कहा कि संविधान ने देश के आत्म-सज़्मान और गरिमा को पक्का किया है। उन्होंने आगे कहा कि संविधान बनाने वाले चाहते थे कि हमारे निजी, डेमोक्रेटिक अधिकार हमेशा सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा मुझे संविधान दिवस के ऐतिहासिक मौके पर आप सभी के बीच आकर बहुत खुशी हो रही है। आज ही के दिन, 26 नवंबर, 1949 को, संविधान भवन के इसी सेंट्रल हॉल में, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का ड्राज़्ट बनाने का काम पूरा किया था। उसी साल इसी दिन, हम भारत के लोगों ने अपना संविधान अपनाया था। आज़ादी के बाद, संविधान सभा ने भारत की अंतरिम संसद के तौर पर भी काम किया। ड्राज़्टिंग कमेटी के चेयरमैन, बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के मुज़्य बनाने वालों में से एक थे। राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाएं, युवा, स्ष्ट्ह्य, स्ज्ञ्ह्य, किसान, मिडिल ज़्लास और उभरता हुआ नया मिडिल ज़्लास भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम को मज़बूत कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना देश की सबसे बड़ी उपलज़्धियों में से एक है। संविधान सदन में संविधान दिवस समारोह के दौरान, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा- स शुभ अवसर पर, हम भारत की संविधान सभा के चेयरमैन डॉ. राजेंद्र प्रसाद; हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर; और संविधान सभा के सभी सदस्यों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी अद्भुत बुद्धिमज़ा, दूर की सोच और अथक मेहनत का नतीजा इतना शानदार संविधान है, जो हर नागरिक के लिए न्याय, समानता, भाईचारा और सज़्मान और गरिमा की गारंटी देता है... संविधान सभा का यह सेंट्रल चैंबर वह पवित्र जगह है जहाँ गहरी चर्चा, बातचीत और विचार-विमर्श के बाद, हमारे संविधान को आकार दिया गया; लोगों की उज़्मीदों को संवैधानिक प्रावधानों में शामिल किया गया। हमारे संविधान के मार्गदर्शन में, पिछले सात दशकों में, हमने सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लक्ष्यों को पाने के लिए नीतियां और कानून बनाए हैं। हमारे संविधान के मार्गदर्शन में, हमने अच्छे शासन और सामाजिक-आर्थिक विकास की एक बदलाव लाने वाली यात्रा शुरू की है. उपराष्टपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि हमारे संविधान की आत्मा ने साबित कर दिया है कि भारत एक है, और यह हमेशा एक रहेगा, उन्होंने संविधान दिवस कार्यक्रम के दौरान दस्तावेज़ की एकजुट करने वाली भावना पर ज़ोर दिया।उन्होंने आगे कहा कि संविधान सामाजिक न्याय, कमज़ोर वर्गों के आर्थिक सशक्तिकरण के प्रति हमारे मज़बूत कमिटमेंट को दिखाता है। उन्होंने कहा, हमारे संविधान बनाने वालों की भावना के अनुसार, हम सभी को इस अमृत काल के दौरान विकसित भारत लक्ष्य की ओर मिलकर काम करना चाहिए। 2015 से, संविधान दिवस या संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, जो 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाने की याद में मनाया जाता है। संविधान के कुछ नियम तुरंत लागू हो गए, जबकि बाकी 26 जनवरी, 1950 को लागू हुए, जब भारत एक रिपज़्लिक बना।

संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने याद दिलाए नागरिक कर्तव्य, कहा-यही हैं मजबूत लोकतंत्र की नींव

२६/११ (संवाददाता): संविधान दिवस पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संविधान बनाने वालों को श्रद्धांजलि दी, उनके विज़न और नागरिक कर्तव्यों के महत्व पर ज़ोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संविधान, %हमें अधिकार देता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि नागरिक के तौर पर हमारे कुछ कर्तव्य हैं। हमें हमेशा उन कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए%।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को नागरिकों से अपने संवैधानिक कर्तव्यों को निभाने का आग्रह किया और कहा कि ये मजबूत लोकतंत्र की नींव हैं। संविधान दिवस पर नागरिकों को संबोधित पत्र में प्रधानमंत्री ने मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र को मजबूत करने की जिज़्मेदारी पर भी जोर दिया और सुझाव दिया कि स्कूल और कॉलेज 18 वर्ष की आयु पूरी करके पहली बार मतदाता बनने वालों का सज़्मान करते हुए संविधान दिवस मनाएं।पीएम मोदी ने महात्मा गांधी के इस विचार को याद किया कि अधिकार कर्तव्यों के निर्वहन से ही प्राप्त होते हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि कर्तव्यों का निर्वहन सामाजिक और आर्थिक प्रगति का आधार है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि नीतियां और आज लिए गए निर्णय आने वाली पीढ़ियों के जीवन को आकार देंगे। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से आग्रह किया कि 'विकसित भारत' के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए वे अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखें। मोदी ने 'एज़्स' पर एक अलग पोस्ट में लिखा, ''हमारा संविधान मानवीय गरिमा, समानता और स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व देता है। यह हमें अधिकारों से सशक्त बनाता है, साथ ही हमें नागरिक के रूप में हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है, जिन्हें हमें हमेशा पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। ये कर्तव्य एक मजबूत लोकतंत्र की नींव हैं।'' उन्होंने संविधान निर्माताओं को भी श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा, ''उनकी दूरदर्शिता हमें विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करती रहती है।

संविधान में आस्था रखकर आगे बढ़ रहा है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत- साय

रायपुर २६/११ (संवाददाता): विष्णुदेव साय आज 75वें संविधान दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित टाउन हॉल में आयोजित हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम में शामिल हुए। मुज़्यमंत्री साय ने उपस्थित जनसमूह के साथ संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया और संविधान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। इस दौरान मुज़्यमंत्री ने संविधान दिवस पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने संविधान पर आधारित लघु फिल्म भी देखी और जनप्रतिनिधियों के साथ इस अवसर को यादगार बनाने के लिए सेल्फी ली।

सर्वोच्च न्यायालय में एसआईआर पर हुई सुनवाई, चुनाव आयोग से 1 दिसंबर तक मांगा गया जवाब

२६/११ (संवाददाता): भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई निर्धारित की है। केरल के मामलों की सुनवाई 2 दिसंबर को तमिलनाडु के मामलों की सुनवाई 4 दिसंबर को और पश्चिम बंगाल के मामलों की सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। बिहार के एसआईआर से संबंधित संबंधित याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी। केरल एसआईआर मामला स्थानीय निकाय चुनावों के कारण एसआईआर प्रक्रिया के स्थगन के कारण उत्पन्न हुआ है। वरिष्ठ

अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने बताया कि इस मामले से संबंधित याचिकाएँ मद्रास उच्च न्यायालय में पहले ही दायर की जा चुकी हैं। राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव आयोग के साथ समन्वय बनाए रखा है, 99 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं को फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं और 50 प्रतिशत से अधिक पहले ही डिजिटल रूप से जमा कर दिए गए हैं। भारत के मुज़्य न्यायाधीश (सीजेआई) ने केरल के एसआईआर के संबंध में एक अंतरिम स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोगों को 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है, और सुनवाई उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित की गई है। तमिलनाडु एसआईआर मामले से जुड़े सभी वकीलों को दस्तावेजों की सॉज़्ट कॉपी प्राप्त होगी और 3 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने होंगे।सुनवाई के दौरान, यह बताया गया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान पश्चिम बंगाल में 23 बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) की मृत्यु हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव कार्यालय से 1 दिसंबर तक विस्तृत जवाब मांगा है और राज्य चुनाव आयोगों और चुनाव आयोग दोनों से जवाब देने का आदेश दिया है।

जीरो टॉलरेंस पर है मोदी सरकार, वैश्विक समर्थन भारत को प्राप्त-गृहमंत्री अमित शाह

नयी दिल्ली २६/११ (संवाददाता): मुंबई में 26/11 हमलों की 17वीं बरसी है, जिसे पाकिस्तान से आए लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद पर भारत की 'ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी' पर ज़ोर दिया। 10 आतंकवादियों का एक ग्रुप 26 नवंबर, 2008 की रात को समुद्री रास्ते से शहर में घुसा और अगले 60 घंटों तक एक के बाद एक कई हमले किए, जिसमें 166 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। ताज और ओबेरॉय होटल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, नरीमन हाउस में यहूदी सेंटर, कामा हॉस्पिटल, मेट्रो सिनेमा और लियोपोल्ड कैफे टारगेट में से थे, ज़्योंकि इन जगहों पर विदेशी यात्री अज़्सर आते-जाते थे।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि मोदी सरकार की आतंकवाद को बिल्कुल न बर्दाश्त करने (जीरो-टॉलरेंस) की नीति स्पष्ट है और पूरा विश्व भारत के आतंकवाद रोधी अभियानों को सराह रहा है तथा उसे व्यापक समर्थन दे रहा है। मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमलों के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शाह ने 'एज़्स' पर एक पोस्ट में कहा कि आतंकवाद किसी एक देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। गृह मंत्री ने कहा, ''वर्ष 2008 में आज ही के दिन आतंकियों ने मुंबई पर कायराना हमला कर वीभत्स और अमानवीय कृत्य किया था।'' उन्होंने कहा, ''मुंबई आतंकी हमलों का डटकर सामना करते हुए अपना बलिदान देने वाले वीर जवानों को नमन करता हूं और इस कायराना हमले में अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शाह ने कहा, ''मोदी सरकार की आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति स्पष्ट है, जिसे पूरा विश्व सराह रहा है और भारत के आतंकवाद विरोधी अभियानों को व्यापक समर्थन दे रहा है।'' गौरतलब है कि 26 नवंबर 2008 को लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादी समुद्र के रास्ते मुंबई पहुंचे और 60 घंटे तक मुंबई को बंधक बनाने के दौरान उन्होंने 18 सुरक्षाकर्मियों सहित 166 लोगों की हत्या कर दी।

साय ने डॉ भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण

रायपुर २६/११ (संवाददाता): सीएम साय ने डॉ भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। डॉ. भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्यप्रदेश के महू जिले में एक महार परिवार में हुआ था। महार जाति को उस समय अछूत समझा जाता था। बाबा साहेब के पिता सेना में थे और नौकरी के सिलसिले में यहां रहा करते थे। उनके पुरखे महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबाडावे गांव से थे।

1906 में भीमराव अंबेडकर की पहली शादी रमाबाई से हुई। रमाबाई ने उनकी पढ़ाई में बहुत मदद की। दोनों के 5 बच्चे थे, इनमें से केवल यशवंत अंबेडकर जीवित रहे।

देश 2047 तक बन जाएगा विकसित राष्ट-ओम बिरला

नयी दिल्ली २६/११ (संवाददाता): लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को कहा कि यदि संविधान का अक्षरश- पालन किया जाए तो भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार हो सकेगा। संविधान सदन (पुराना संसद भवन) के केंद्रीय कक्ष में आयोजित संविधान दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिरला ने कहा कि लंबे विचार-विमर्श के बाद संविधान निर्माताओं ने 1949 में इसी दिन मुज़्य दस्तावेज को अंगीकार किया था, जिससे भारत के लिए एक जीवंत लोकतंत्र बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। बिरला ने इस बात उल्लेख किया कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो प्रत्येक नागरिक की आवश्यकता का ज़्याल रखता है और इसमें निहित सिद्धांतों का पालन करना सबका कर्तव्य है।

कैबिनेट बैठक में चार बड़े फैसले, रेयर अर्थ मैग्नेट विनिर्माण को बढ़ावा देगा भारत

नई दिल्ली २६/११ (संवाददाता): यूनियन कैबिनेट ने बुधवार 26 नवंबर को बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कुल 9,919 करोड़ रुपये की चार बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन चार परियोजनाओं में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम भी शामिल है। इसके तहत तहत आने वाले 7 सालों में 7,280 करोड़ रुपये की रेयर अर्थ की खोज की जाएगी। इस स्कीम का मकसद इंपोर्ट पर निर्भरता कम करना और हाई-टेज़्नोलॉजी एप्लीकेशन में भारत की क्षमताओं को बढ़ाना है।

भारी उद्योग मंत्रालय ने कहा, इस पहल का मकसद भारत में 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MTPA) इंटीग्रेटेड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (REPM) मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करना है, जिससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और भारत ग्लोबल REPMमार्केट में एक अहम खिलाड़ी के तौर पर उभरेगा। मंत्रालय ने आगे कहा, REPM सबसे मज़बूत तरह के परमानेंट मैग्नेट में से एक हैं जो इलेज़्ट्रिक गाड़ियों, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेज़्ट्रॉनिज़्स, एयरोस्पेस और डिफेंस एप्लीकेशन के लिए जरूरी हैं।यह स्कीम इंटीग्रेटेड REPM मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने में मदद करेगी, जिसमें रेयर अर्थ ऑज़्साइड को मेटल में, मेटल को एलॉय में और एलॉय को फिनिश्ड REPM में बदलना शामिल है। इस स्कीम में ग्लोबल कॉज़्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस के ज़रिए पांच बेनिफिशियरी को टोटल कैपेसिटी देने का प्लान है। हर बेनिफिशियरी को 1,200 स्र्ह्लक्क तक की कैपेसिटी दी जाएगी।

वर्तमान समय में चीन ग्लोबल रेयर अर्थ मैग्नेट सप्लाई चेन पर हावी है। उसने एक बेहद कड़े लाइसेंसिंग सिस्टम के जरिए जियोपॉलिटिकल पॉलिसी के टूल के तौर पर अपने कंट्रोल का इस्तेमाल किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा और गुजरात के कोस्टलाइन पर रेयर अर्थ डिपॉजिट हैं, गुजरात और महाराष्ट्र के पहाड़ी इलाकों में भी ऐसा ही है। परमानेंट मैग्नेट हल्के और भारी रेयर अर्थ के कॉज़्बिनेशन से बनाए जाएंगे। इन मिनरल को माइन, प्रोसेस और रिफाइन करना मुश्किल है। मंत्री ने कहा, ट्रेड डील में भी रेयर अर्थ्स का जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक महत्व है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन को भी हाल ही में दुनिया भर से मटीरियल सोर्स करने की मंज़ूरी दी गई थी।उन्होंने यह भी कहा कि भारत REPM प्रोग्राम के जरिए ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर काम करेगा। ऑस्ट्रेलिया के पास रेयर अर्थ्स के बड़े भंडार हैं जिनका अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, जबकि जापानी प्रमुख टेक डेवलप कर रहे हैं।

विविध समाचार

नाम बदलकर मतदाता बनने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों में दिख रहा खौफ, रिवर्स माइग्रेशन चरम पर

कोलकाता २६/११ (संवाददाता): पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के चलते सैकड़ों अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के अपने देश लौटने की खबरों के बीच, राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने आज मुर्शिदाबाद का दौरा किया। इससे पहले उन्होंने उज्ञर 24 परगना के हकीमपुर सीमा चौकी पर हालात का जमीनी जायजा लिया था। राज्यपाल ने स्थानीय लोगों से बातचीत की और बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की। राज्यपाल ने कहा कि स्ङ्क्र एक अहम और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इससे जुड़े मामलों पर विभिन्न व्याज्ञ्याएं सामने आ रही हैं, इसलिए वे जमीनी सच्चाई अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। हम आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अवैध घुसपैठियों में व्यापक भय फैलने के कारण बंगाल के कई क्षेत्रों—विशेषकर नदिया, मुर्शिदाबाद और उज्ञर 24 परगना—में रिवर्स माइग्रेशन तेज़ हुआ है और बड़ी संज्ञ्या में घुसपैठिये सीमा पार कर लौटने की कोशिश कर रहे हैं।

देखा जाये तो पश्चिम बंगाल की सीमाओं पर आज जो दृश्य दिखाई दे रहा है वह किसी सामान्य घटनाक्रम का परिणाम नहीं है। यह उस भय की उपज है, जो वर्षों से ढीली पड़ी व्यवस्थाओं पर पहली बार किसी सज़्त प्रशासनिक कार्रवाई की दस्तक मात्र सुनकर पैदा हुआ है। एसआईआर कोई दंडात्मक अभियान नहीं, बल्कि एक साधारण, नियमित चुनावी प्रक्रिया है। लेकिन इस साधारण प्रक्रिया ने जिस असाधारण प्रतिक्रिया को जन्म दिया है, वही बंगाल के बड़े और वास्तविक संकट—घुसपैठ, जनसंज़्या असंतुलन और वोट बैंक के गठजोड़ को उजागर करता है।कड़वा सत्य यह है कि बंगाल के एक-एक जिले में लाखों अवैध घुसपैठियों ने अपने नाम बदलकर, उपनाम बदलकर, पहचान बदलकर भारतीय मतदाता सूची में प्रवेश पा लिया है। कुछ आँकड़े बताते हैं कि करीब 2.68 लाख लोगों ने अपने मुस्लिम नाम हटाकर हिन्दू उपनाम जोड़ लिए, ताकि वे स्थानीय दिखें और मतदाता सूची में जगह बना सकें। यह आंकड़ा भयावह है और स्वयं इस बात का प्रमाण है कि घुसपैठ अब केवल सुरक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि राजनीतिक संरचना को प्रभावित करने वाली संगठित जनसांज़्यिकीय रणनीति बन चुकी है।इस तरह की भी रिपोर्टें हैं कि बंगाल के कई इलाकों में घरों में ताले पड़े हैं, पूरा-पूरा मोहल्ला खाली दिखाई देता है, लोग रातों-रात सीमा के उस पार भाग रहे हैं। ये दृश्य यूँ ही नहीं बने, ये इसलिए बन सके ज़्योंकि वर्षों से इस अवैध प्रवासन को न केवल अनदेखा किया गया, बल्कि कई बार राजनीतिक संरक्षण भी दिया गया। कुछ दलों ने इसे वोट बैंक के रूप में पोषित किया, स्थानीय प्रशासन ने आंखें मूँद लीं और परिणामस्वरूप सीमावर्ती जनसंज़्या धीरे-धीरे विस्थापित और भयग्रस्त होती गई। इस पूरे परिदृश्य में राज्यपाल का सीमा पर जाकर स्थिति देखना प्रतीकात्मक ही नहीं, बल्कि अत्यंत आवश्यक कदम है। जब एक संवैधानिक पदाधिकारी को खुद कहना पड़े कि गलत सूचना फैलाकर लोगों में डर पैदा किया जा रहा है, तो यह समझ जाना चाहिए कि शासन-व्यवस्था में कहीं न कहीं गहरी दरार उत्पन्न हो चुकी है। यह केवल गलत सूचना का मामला नहीं, बल्कि उस असुरक्षा का मामला है जिसका लाभ राजनीतिक संरक्षण प्राप्त घुसपैठिये वर्षों से उठाते आ रहे थे और पहली बार उन्हें लगता है कि प्रक्रिया भी उनके लिए खतरा बन सकती है। सवाल यह है कि ऐसे भय का जन्म कैसे हुआ? ज़्या इसलिए कि इन लोगों के पास दस्तावेज़ नहीं? ज़्या इसलिए कि ये सच्चे नागरिक नहीं? या इसलिए कि वर्षों से इन्हें बिना अधिकार, बिना नियम, बिना पहचान भारत में रहने दिया गया? इस भय का उज़र इन्हीं सवालों में छिपा है। यह साफ दिख रहा है कि भले ही सरकारें बदलती रहीं, लेकिन बंगाल में अवैध घुसपैठ का मुद्दा स्थायी, संरचनात्मक और तेज़ी से बढ़ता हुआ संकट रहा है। स्ङ्क्र यदि केवल कागज़ी कार्रवाई है और इसके चलते ही हजारों लोग पलायन कर रहे हैं, तो कल्पना कीजिए कि यदि एक व्यापक, कठोर और राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने वाला पहचान सत्यापन अभियान शुरू किया जाए, तो कितनी वास्तविकता उजागर होगी। यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू है— घुसपैठ का सांस्कृतिक असर। बंगाल के कई इलाकों में स्थानीय लोग अल्पसंज़्यक बन गए हैं। केशवपुर जैसे क्षेत्रों में जनसंज़्या घुसपैठियों की बताई जा रही है। यह स्थिति केवल जनसंज़्या का मुद्दा नहीं, बल्कि भाषा, सुरक्षा, रोजगार और सांस्कृतिक अस्तित्व का सवाल बन चुकी है। देखा जाये तो हालात ऐसे विकट हैं कि सिर्फ स्ङ्क्र से समस्या हल नहीं होगी। इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, राष्ट्रीय नीति और कठोर कानून की आवश्यकता है। देश को ह्रष्ट (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) जैसे ठोस उपायों की स्पष्ट, चरणबद्ध और निष्पक्ष रूपरेखा चाहिए। घुसपैठ सिर्फ बंगाल का नहीं, बल्कि पूरे भारत का मुद्दा है—असम, त्रिपुरा, अरुणाचल, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, हर जगह इसकी गूँज सुनाई देती है। सरकारें यदि केवल चुनावी लाभ-हानि के आधार पर निर्णय लेंगी, तो इस देश की सीमाओं की सुरक्षा, नागरिकों की पहचान और जनसंज़्या संतुलन कभी स्थिर नहीं हो पाएगा। यह राजनीतिक साहस का समय है और साहस वही है जो कतरा-कतरा वोट की राजनीति से ऊपर उठकर एक राष्ट्रीय समाधान बनाए।

राष्ट्रपति मुर्मू ने जारी किया 9 भाषाओं में डिजिटल संविधान, राष्ट्रवाद पर जोर

नयी दिल्ली २६/११ (संवाददाता): राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित संविधान दिवस कार्यक्रम के दौरान 75वें संविधान दिवस के उपलक्ष्य में नौ भाषाओं - मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और असमिया - में भारतीय संविधान का डिजिटल संस्करण जारी किया। कार्यक्रम के दौरान एक स्मारक पुस्तिका भारत के संविधान में कला और सुलेख का भी विमोचन किया गया। संविधान दिवस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य नेता शामिल हुए। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि संविधान दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी के बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आज ही के दिन, 26 नवंबर, 1949 को, संविधान भवन के इसी केंद्रीय कक्ष में, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने का कार्य पूरा किया था। उसी वर्ष, आज ही के दिन, हम भारत के लोगों ने अपना संविधान अंगीकार किया था। स्वतंत्रता के बाद, संविधान सभा ने भारत की

अंतरिम संसद के रूप में भी कार्य किया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर, हमारे संविधान के प्रमुख निर्माताओं में से एक थे। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि तीन तलाक से जुड़ी सामाजिक बुराई पर अंकुश लगाकर, संसद ने हमारी बहनों और बेटियों के सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा कर सुधार, वस्तु एवं सेवा कर, देश के आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया। अनुच्छेद 370 को हटाकर, देश के समग्र राजनीतिक एकीकरण में बाधा बन रही एक बाधा को दूर किया गया। नारी शक्ति बंधन अधिनियम महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के एक नए युग की शुरुआत करेगा... इस वर्ष, 7 नवंबर से, हमारे राष्ट्रगान, वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव आयोजित किया जा रहा है। संविधान सदन में संविधान दिवस समारोह के दौरान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा- 卐इस पावन अवसर पर, हम भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद, हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के सभी सदस्यों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी अद्भुत बुद्धिमज्ञा, दूरदर्शिता और अथक परिश्रम के परिणामस्वरूप एक ऐसा भव्य संविधान निर्मित हुआ, जो प्रत्येक नागरिक के लिए न्याय, समानता, बंधुत्व और सज़्मान की गारंटी देता है। संविधान सभा का यह केंद्रीय कक्ष वह पवित्र स्थल है जहाँ गहन विचार-विमर्श, संवाद और विचार-विमर्श के बाद हमारे संविधान का निर्माण हुआ; जन आकांक्षाओं को संवैधानिक प्रावधानों में समाहित किया गया।

ममता का भाजपा पर तीखा प्रहार,मुझे हराने का दम नहीं, चुनाव आयोग अब बीजेपी कमीशन

कोलकाता २६/११ (संवाददाता): विधानसभा चुनाव अभी कुछ महीने दूर हैं। उससे पहले बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सियासत गरमा गई है। इसी माहौल में मंगलवार को मुज़्यमंत्री ममता बनर्जी ने बोंगांव में एक सभा की। एसआईआर विरोधी रैली में ममता ने कहा कि भाजपा राजनीतिक रूप से मेरा मुकाबला नहीं कर सकती और न ही मुझे हरा सकती है। उन्होंने कहा कि 'इलेज़्शन कमीशन' अब एक निष्पक्ष संस्था नहीं रह गई है, यह 'बीजेपी कमीशन' बन गई है। बनर्जी ने सवाल किया कि ज़्या भाजपा शासित राज्यों में एसआईआर का आयोजन यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार स्वीकार करती है कि वहां %घुसपैठिया% मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मैं बीरभूम में पैदा हुई, वरना मुझे भी बांग्लादेशी कहते। अपने भाषण की शुरुआत में ममता ने हेलीकॉप्टर को लेकर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा, मैं हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं करती। मैं कार से चलती हूँ। राज्य सरकार के पास एक हेलीकॉप्टर है। यह किराए पर है। मुझे सुबह 10 बजे यहाँ आना था। सुबह अचानक पता चला कि हेलीकॉप्टर नहीं जाएगा। चुनाव से पहले ही झगड़ा शुरू हो गया था। लेकिन मेरे लिए यह अच्छा रहा। रास्ते में कई जगह घूमा। लोगों से बातें कीं। उन्होंने दावा किया कि मैंने भाजपा से कहा कि मैं जो खेल खेलूँगी, उसमें मुझे कोई छू नहीं सकता। गलियों में घूमने से मेरा संपर्क और भी लोगों से हुआ है। एसआईआर के बारे में उन्होंने कहा कि एसआईआर कराने में तीन साल लगते हैं। 2002 में भी यही हुआ था। हमने कहा था कि कोई भी वैध मतदाता छूटेगा नहीं। अब नियम बदल रहे हैं। आयोग तय कर रहा है कि सरकार में कौन बैठेगा। चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए। पहले मुझे आधार कार्ड मिला था। वहाँ सबने पैसे खर्च किए।

पांचजन्य: शंखनाद के साथ पीएम मोदी ने कुरुक्षेत्र में जगाया आस्था का ज्वार, महाभारत अनुभव केंद्र का किया भ्रमण

कुरुक्षेत्र २६/११ (संवाददाता): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण के पवित्र शंख के सज़्मान में निर्मित %पांचजन्य% का उद्घाटन किया। उनके साथ हरियाणा के मुज़्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी थे। इसके बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने महाभारत अनुभव केंद्र का दौरा किया, जो एक गहन अनुभवात्मक केंद्र है, जिसमें महाभारत के महत्वपूर्ण प्रसंगों को दर्शाने वाली कलाकृतियाँ हैं, जो इसके स्थायी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालती हैं। प्रधानमंत्री मोदी नौवें सिख गुरु, गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री पूज्य गुरु के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। गुरु तेग बहादुर के 350वें

शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में, भारत सरकार एक वर्ष तक चलने वाला स्मरणोत्सव मना रही है।

शाम लगभग 5=45 बजे, प्रधानमंत्री भारत के सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक, ब्रह्म सरोवर में दर्शन और पूजा करेंगे, जिसे श्रीमद्भगवद्गीता के दिव्य प्रकटीकरण से जुड़ा माना जाता है।

यह यात्रा कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के साथ मेल खाती है, जो वर्तमान में 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के 191 फुट ऊँचे शिखर पर भगवा ध्वज फहराने के बाद कुरुक्षेत्र पहुँचे, जो मंदिर निर्माण के पूरा होने का प्रतीक है।

धर्म ध्वज पर तीन पवित्र प्रतीक, सूर्य और कोविदर वृक्ष हैं, जिनमें से प्रत्येक सनातन परंपरा में निहित गहन आध्यात्मिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। समकोण त्रिभुजाकार ध्वज 10 फीट ऊँचा और 20 फीट लंबा है। कोविदर वृक्ष मंदार और पारिजात वृक्षों का एक संकर वृक्ष है, जिसे ऋषि कश्यप ने बनाया था, जो प्राचीन पादप संकरण को दर्शाता है। सूर्य भगवान राम के सूर्यवंश का प्रतिनिधित्व करता है और शाश्वत आध्यात्मिक ध्वनि है।

बाबर की औलादों को भारत में रहने का हक नहीं-गिरिराज

नयी दिल्ली २६/११ (संवाददाता): केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक द्वारा %बाबरी मस्जिद% पर की गई टिप्पणी को लेकर उसकी कड़ी आलोचना की और कहा कि ऐसी टिप्पणियों से साफ़ पता चलता है कि बंगाल में सज़ारूढ़ पार्टी घुसपैठियों के वोट बैंक पर निर्भर है।

पत्रकारों से बात करते हुए, गिरिराज सिंह ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के विधायकों की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे लोगों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सिंह ने कहा कि बंगाल बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का गढ़ बन गया है। उन्हें पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज़ मुहैया कराए गए हैं, जिससे वे अवैध रूप से रह सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस इन घुसपैठियों के वोट बैंक पर निर्भर है। ममता बनर्जी इन अवैध घुसपैठियों को खुश करने के लिए हर असंवैधानिक और हिंदुओं के ख़िलाफ़ काम करती हैं।

टीएमसी विधायकों का बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण का दावा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो लोग खुद को बाबर और औरंगज़ेब की औलाद कहते हैं, उन्हें भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह टिप्पणी टीएमसी विधायक कबीर द्वारा यह घोषणा करके विवाद खड़ा करने के बाद आई है कि वह 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखेंगे, जो अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस के 33 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में है। उन्होंने कहा, हम 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखेंगे।

इसे पूरा होने में तीन साल लगेंगे। इस कार्यक्रम में विभिन्न मुस्लिम नेता भाग लेंगे। अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवादित ढांचे को 6 दिसंबर, 1992 को कार सेवकों ने ध्वस्त कर दिया था।

विधानसभा चुनाव से पहले हिंदुओं का दिल जीतने की कोशिश? ममता कैबिनेट ने सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर के निर्माण को दी मंजूरी

कोलकाता २६/११ (संवाददाता): पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने एक बड़े प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी, जिससे सिलीगुड़ी के माटीगाड़ा में एक भव्य महाकाल मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ़ हो गया। यह फ़ैसला मुज़्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा अज़्टूबर में उज़र बंगाल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के दौरान की गई घोषणा के बाद लिया गया है, जहाँ उन्होंने दार्जिलिंग के प्रतिष्ठित महाकाल मंदिर की शैली में मंदिर बनाने का संकल्प लिया था।

कैबिनेट बैठक के बाद, विज़ राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने मीडिया को इस फ़ैसले की जानकारी दी। उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार माटीगाड़ा के लक्ष्मी टाउनशिप क्षेत्र में मौजूदा पट्टाधारकों से 25.15 एकड़ ज़मीन अधिग्रहित करेगी। इसमें से 17.41 एकड़ ज़मीन भूमि एवं भूमि सुधार विभाग से पर्यटन विभाग को हस्तांतरित की जाएगी, जबकि शेष ज़मीन चरणों में सौंपी जाएगी। सरकार की योजना इस पूरे क्षेत्र को आगामी महाकाल मंदिर के आसपास एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की है।

भट्टाचार्य ने कहा कि कैबिनेट का यह फ़ैसला मुज़्यमंत्री के वादे को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। मुज़्यमंत्री ने वादा किया था कि उज़र बंगाल में एक महाकाल मंदिर बनाया जाएगा। उस वादे पर अमल करते हुए, कैबिनेट ने सर्वसज़्मति से भूमि हस्तांतरण को मंज़ूरी दे दी। मुज़्यमंत्री बनर्जी ने पहले ही खुलासा कर दिया था कि मंदिर परिसर में क्षेत्र की सबसे बड़ी भगवान शिव की मूर्ति स्थापित की जाएगी, जिससे इसकी पर्यटन अपील और बढ़ेगी। यह कदम राज्य सरकार द्वारा की गई अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक पहलों के बाद उठाया गया है, जिसमें दीघा में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण और न्यू टाउन में %दुर्गा आंगन% की योजना शामिल है।

मंदिर परियोजना के अलावा, कैबिनेट ने उज़र बंगाल के डाबग्राम क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेंटर के निर्माण को भी मंज़ूरी दी। यह सुविधा तीस्ता टाउनशिप क्षेत्र में एशियाई राजमार्ग 2 से सटी 10 एकड़ ज़मीन पर बनाई जाएगी। भट्टाचार्य ने बताया कि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर होने वाले आयोजनों और सज़्मेलनों को बढ़ावा देने के लिए लंबे समय से इस तरह के स्थल की मांग की जा रही थी।

कलिंग समाचार
THE KALINGA SAMACHAR
(A Hindi Daily News Paper)
PUBLISHED FROM ODISHA, JHARKHAND & CHATTISHGARH
FOR NEWS AND ADVERTISEMENT CONTACT
AT: QRS. NO. B/204, SECTOR-16
ROURKELA, PH. 0661-2646999
PRAKASH KUMAR DHAL (EDITOR)
E-mail: thekalingasamachar@gmail.com

विविध समाचार

क्यों खराब हो जाता है आपका फ्रिज

क्या आपका भी फ्रिज बार- बार खराब हो जाता है? कई लोग को पता भी नहीं होता कि उनका फ्रिज किन गलतियों के कारण खराब हो गया है। ऐसे में आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताने वाले है कि कैसे आप अपने फ्रिज को खराब होने से बचा सकती है।

कई बार हमारी छोटी गलती के कारण हमारा काफी बड़ा नुकसान हो जाता है। क्या आपका भी फ्रिज बार– बार खराब हो जाता है? कई लोग को पता भी नही होता कि उनका फ्रिज किन गलतियों के कारण खराब हो गया है। ऐसे में आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताने वाले है कि कैसे आप अपने फ्रिज को खराब होने से बचा सकती है। साथ ही यह भी बताने वाले है कि फ्रिज कैसे खराब हो जाता है।

सफाई सही से करें

कई बार फ्रिज में कोई सामान गिर जाता है और हम इसकी सफाई सही तरीके से नही करते है। फ्रिज की सफाई सही तरीके से करना काफी ज्यादा जरूरी है। ऐसे में फ्रिज में फंगस लग जाता है और मिनटों में हमारा महंगा फ्रिज खराब होने लगता है और हमे पता भी नही चलता। कई बार हम इसके लिए कंपनी में शिकायत करते है। इस दौरान गलती किसी और की नही बल्कि हमारी ही होती है। कई बार हम फ्रिज में जरूरत से ज्यादा सामान रख देते है। ऐसे में भी हमारा फ्रिज खराब हो जाता है। फ्रिज की सही तरीके से केयर करने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आप ज्यादा सामान रखती है तब भी आपका फ्रिज खराब हो सकता है।

फ्रिज को लंबे समय तक खुला ना छोड़े

कई बार हम फ्रिज को लंबे समय तक खुला छोड़ देते है। इसके कारण भी हमारा फ्रिज खराब हो जाता है। अगर आप भी अपने पैसे फ्रिज के रिपेयरिंग में बर्बाद नही करना चाहती है तो आपको इन बातों का खास ख्याल रखना होगा।

बाहर जाते वक्त फ्रिज बंद ना करें

अगर आप बाहर जाने का प्लान बना रही है तो आपको अपने फ्रिज को पूरे तरीके से बंद नही करना चाहिए। कई बार इसके कारण भी फ्रिज खराब हो जाता है। आगे से आपको इस बात का खास ख्याल रखना होगा। थोड़ी सी बिजली बचाने के चक्कर में हमारा काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है।

ना करें पैसों से जुड़ी ये गलतियां

अक्सर महिलाओं की ये समस्या होती है कि घर का खर्च ज्यादा हो रहा है और पैसों से जुड़ी बचत नहीं हो पा रही है। यहां निवेश और बचत की नहीं खर्च की बात हो रही है। घरों में आजकल की व्यस्त लाइफस्टाइल कुछ ऐसी हो गई है कि लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि उनका इतना खर्च आखिर कैसे बढ़ गया है। ये सब कुछ पैसे से जुड़ी कुछ गलतियों के कारण होता है।

आम तौर पर यही देखा जाता है कि पति और पत्नी एक दूसरे से इसके बारे में बात नही करते। पत्नी घर संभाल रही हो या फिर बाहर काम कर रही हो तो भी इसके बारे में बाते नही की जाती। बच्चे अगर पढ़ने की उम्र में हैं या टीनएज हो गए हैं तो उन्हें भी अक्सर घर पर ये नही बताया जाता है कि निवेश और बचत की जरूरत क्या है। हफ्ते में कम से कम एक बार सभी को बैठकर घर और पैसे के खर्च से जुड़ी बातें करनी चाहिए। इससे वो खर्च भी सामने आ जाता है जिसका शायद अंदाजा भी नही होता। ये घर का बजट बनाने में भी मददगार साबित हो सकता है।

पहले खर्च फिर जो बचा वो निवेश

हमारी भारतीय संस्कृति में एक आम कहावत है कि 'जितनी चादर है उतना ही पैर पसारो'। ये बहुत अच्छा कथन है, लेकिन इसे हमें थोड़ा सा बदलना होगा क्योंकि हम हमेशा जितना खर्च है उतना कर लो और उसके बाद जो बचा वो बचत। इससे समस्या ये होती है कि जरूरत से अधिक खर्च भी हो जाता है और बचत कम रह जाती है। इसे थोड़ा सा बदलने की जरूरत है और कमाई के बाद एक निश्चित बचत और उसके बाद जितना बचा उसे खर्च करना चाहिए। ये बजट आसानी से बन सकता है कि महीने में कितनी बचत की जा सकती है।

बचत और निवेश का अंतर न समझना

मान लीजिए आप हर महीने की आय में से कुछ पैसे बचा लेते हैं, लेकिन क्या इन पैसों को बचाने से सिर्फ काम हो जाता है? जी नहीं, बचत और निवेश में काफी अंतर है जिसे समझने की जरूरत है। पैसे ड्रॉअर में पड़े रहें या फिर वो बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रखा है तो उससे हमारे भविष्य के लिए कोई फायदा हो रहा है? बिलकुल नहीं। तन्वी जी का कहना है कि उनके पास बहुत से लोग आते हैं और वो यहीं मात खा जाते है। उन्हें निवेश इस बारे में सोचकर करना चाहिए कि भविष्य में ये कितना रिटर्न देगा।

अपनी बचत और निवेश को ऑटोमैटिक मोड पर नहीं डालना

बैंक की आरडी या एफडी जिसका ऑटोमैटिक पैसा कटता है वो ज्यादा सही है। भले ही बचत और निवेश का कोई भी मोड हो पैसा ऑटोमैटिक हर महीने कटना चाहिए। कारण ये है कि अगर बचत हर वक्त नहीं होगी तो हम उस कमाई को खर्च करने के लिए उत्सुक रहेंगे। अकाउंट में या जेब में ज्यादा पैसा होने का मतलब है कि उसे खर्च करने का लालच भी बढ़ जाएगा। अगर सैलरी आते ही एक अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद से पैसे निवेश कर देंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित होगा।

अपने पैसे को अलग–अलग जगह न निवेश करना

पैसा है आपके पास तो क्या हर बार वो एक ही तरह से निवेश किया जाएगा? कई लोग सिर्फ FD कराते रहते है, कुछ को पोस्ट ऑफिस की NSC अच्छी लगती है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि पैसे के साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता। कारण ये है कि अगर एक ही तरह से पैसा निवेश होगा तो खतरे की स्थिति में एक ही साथ उसके खर्च होने या फिर डूब जाने की गुंजाइश भी होती है।

फाइनेंशियल भाषा से डरना और रिस्क न लेना

इंसान का दिमाग जो चीज समझ नही पाता वो उससे हमेशा डरता रहता है और ये बहुत आम घटना है कि लोग खुद को फाइनेंशियल भाषा सिखा नहीं पाते। ऐसे में उन्हें जानकारी न के बराबर रहती है। होता ये है कि ऐसी स्थिति में निवेश के समय हम बहुत ज्यादा सोच विचार में लग जाते है और कई बार डर के कारण रिस्क नहीं ले पाते। इससे बाद में नुकसान होने की गुंजाइश है।

कर्ज को न समझना

बहुत से लोगों के पास होम लोन होता है, कार का लोन होता है, क्रेडिट कार्ड से खर्च होता है। अर्थव्यवस्था में कर्ज की दरें लगातार बढ़ती और घटती रहती है। ऐसे में हमारे कर्ज पर भी असर पड़ता है। किसी भी तरह के लोन को हमेशा फाइनेंशियल एक्सपर्ट से हर साल रिव्यू करवाना चाहिए। क्या पता ब्याज की दर इससे कम हो सके। इसी तरह से क्रेडिट कार्ड सबसे महंगा तरीका है ऐसे में कई बार वो बहुत महंगा पड़ जाता है। कोशिश करें कि हर वक्त क्रेडिट कार्ड निकालने से बचें।

अपनी पसंद और फिटिंग के मुताबिक खरीदें ट्रैंडी जींस

जींस एक ऐसी कॉमन ड्रेस है, जो हर लड़की के वार्डरोब में जरूर मौजूद होती है। बाजार में कई स्टाइलिश जींस आ चुकी है, जिन्हें आप अपनी पसंद और फिटिंग के मुताबिक खरीद सकती हैं। जींस खरीदने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आजकल किस पैटर्न की जींस का चलन ज्यादा है। आज हम आपको जींस की इन्हीं वैरायटी के बारे में बता रहे है जिनके बारे में जानकर आपको अपनी पसंद की जींस खरीदने में आसानी होगी.

रिप्ड जींस

रिप्ड जींस एक दशक से फैशन ट्रेंड में बनी हुई है। कॉमन यंग गर्ल्स से लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस सभी में इसका क्रेज है। शायद ही कोई लड़की होगी जिसके वार्डरोब में रिप्ड जींस न हो। एक दशक पहले ट्रेंड में आई ये जींस आज भी लड़कियों की पहली पसंद बनी हुई है। इसमें जींस के कई हिस्सों में कुछ स्लिट्स या कट्स बने होते है। कॉमन लैंग्वेज में इसे फटी जींस भी कहते है। अगर आपके पास कोई पुरानी जींस है, जिसे आप नहीं पहनती तो उसे ब्लेड से कट करके रिप्ड जींस का लुक दे सकती है। रिप्ड जींस को आप लॉन्ग कुर्ती या फिर किसी भी टॉप के साथ पियर कर सकती है। ये आपको कूल और स्टाइलिश लुक देगी।

बैगी जींस

बैगी जींस अपने लूज साइज की वजह से काफी कंफर्टेबल होती है। दो से तीन दशक पहले इस पैटर्न की जींस का काफी चलन था। एक बार फिर से इसका ट्रेंड लौट आया है। यही वजह है कि सैलेब्स में भी ये जींस काफी पॉपुलर है। ट्रैवलिंग के दौरान या कहीं आने–जाने के लिए एक्ट्रेस इसे कैरी किए नजर आती रही हैं।

पैच वर्क जींस

इन दिनों पैच वर्क जींस भी काफी पॉपुलर है। यंग गर्ल्स से लेकर सैलेब्स इसे पहने नजर आती रहती है। ये जींस अलग–अलग रंग के जींस के चौकोर टुकड़ों को एक साथ पैच करके बनाई जाती है, जो देखने में काफी यूनीक और कूल लगती है।

बेल बॉटम जींस

पुराने जमाने में आपने हीरो–हीरोइन को फिल्मों में नीचे से खुली पैंट या जींस पहने देखा होगा। इस स्टाइल को बेल बॉटम स्टाइल कहते है। आजकल बेल बॉटम जींस का फैशन फिर से लौट आया है। ये जींस काफी कंफर्टेबल होती है। यंग गर्ल्स से लेकर वर्किंग वुमन बेल बॉटम जींस पहनना पसंद कर रही है।

स्किन फिट जींस

इसके नाम से ही क्लियर है कि ये जींस कैसी होगी। ये पूरी तरह स्किन टाइट होती है। ज्यादातर लड़कियां स्किन फिट जींस पहनना पसंद करती है, लेकिन अगर कंफर्ट की बात करें तो ये उतनी आरामदायक नहीं होती। तब भी इस जींस का क्रेज लड़कियों में बना हुआ है। इसे आप अपनी मनपसंद कुर्ती या फिर टॉप के साथ कैरी कर सकती है।

व्यक्तिगत रिश्ते बनाएं ताकि काम एवं जीवन में सहजता आए

आज आप जितना कर सकती है, उससे अधिक करने की कोशिश न करें। अपनी गतिविधियों की छंटनी शुरू कर दीजिए और फिर अपनी कार्य-सूची पर पुनर्विचार कीजिए। जो चीजें बेकार एवं महत्वहीन हैं, उन्हें बाहर कर दीजिए। आप जो भी कर सकती है या करना चाहती है, उन तमाम चीजों को एक ही दिन में करने का प्रयास न करें। सबसे जरूरी चीज पर नजर रखें एवं प्राथमिकता के आधार पर उन्हें करें।

एक समय में एक ही काम

अपना समय केवल उन्हीं चीजों पर खर्च करें, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। दो या उससे अधिक काम एक साथ करने से तौबा करें, तब भी जब चीजें आसान लगती हो या लगता हो कि आप कर लेंगी। जब आप एक से अधिक काम एक ही बार में करती हैं तो आपका ध्यान बंट जाता है। आप एकाग्रता खो देती है, जो कि बेहतर प्रदर्शन के लिए जरूरी है।

कुछ उदाहरण

यदि आप एक साथ खाती एवं पढ़ती है तो आपका कुछ ध्यान पढ़ने पर और कुछ खाने पर होता है। आप कोई भी चीज ढंग से नहीं कर पाती हैं। जब आप टहलती हैं तो टहलें, जब आप बैठती है तो बैठें। भटके नहीं। जब ड्राइव करें तो पूरा ध्यान रोड पर रखें। काफी ऊंची आवाज में संगीत सुनना या चालक एवं यात्री के बीच की बातचीत कई सड़क हादसों का कारण होती है। यदि आप यात्री है तो चालक को गाड़ी चलाने दें न कि उससे बातचीत करें।

पांच गुण होना महत्वपूर्ण

किसी भी स्त्री या पुरुष में पांच गुण होना चाहिए। ये है– शिष्टाचार, उदारता, लगन, संकल्प एवं दया भाव। शिष्टाचार से आप बेइज्जती को अनदेखा कर सकती है, उदारता से सबको जीत सकती है। लगन से लोग आप पर विश्वास करेंगे और संकल्प एवं दया भाव से सफलता प्राप्त कर सकती है।अच्छी संगत, अच्छी किताबें एवं प्रार्थना– ये तीन चीजें किसी मनुष्य को तीनों लोकों का सम्राट बनाती हैं।

सफलता नैसर्गिक नहीं होती

सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया नैसर्गिक नही है। सफलता हमें विरासत में नहीं मिलती। इसे हम अपने प्रयासों से पैदा करते है। यह हमारे कठिन परिश्रम एवं क्रियाओं की पुनरावृत्ति का काल होता है। संघर्ष जीवन है और जीवन की क्रियाएं ही इसे कर सकती है। हमें केवल सपने देखने वाला नहीं बल्कि आगे बढ़कर उसे करने वाला बनना चाहिए।

सेमिनारों में कुछ नहीं

हम समय–समय पर प्रेरित करने वाले लोगों से मिलते रहते है या सेमिनारों में ऐसे भाषण सुनते रहते हैं। इस प्रकार के पारस्परिक क्रिया से हमें अपने तरीकों को सुधारने एवं काम करने की शैली को और बेहतर करने के उपाय मिलते है। हम उनको अपनाते है और महसूस करते हैं कि अपने आप को और बेहतर करें एवं जीवन में बदलाव लाने का रहस्य पा लिया है। यह पूरी गहमागहमी दो–चार दिनों में खत्म हो जाती है और हम फिर वहीं होते हैं जहां हम थे।

ऊर्जा, समय व पैसे बचायें

याद रखिये सेमिनार एवं कार्यशाला में भाग लेना समय, ऊर्जा और पैसे की बर्बादी है, यदि हम उन चीजों को नही अपनाते, जो वे हम तक पहुंचाना चाहते हैं। यदि आपको कोई बेहतरीन आइडिया मिलता है तो आप अपने आप से पूछिए कि आप इससे क्या करने जा रहे हैं और आप इसे कैसे करेंगे। सभी बातों को लिखिए और फिर निर्णय लीजिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। किन उपायों को लागू करना है, उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए और सब कुछ करने के लिए समय सीमा तय करनी चाहिए।

कलिंग समाचार

संपादकीय

गुरूवार 27 नवंबर 2025

गुजरात से बड़ी लड़ाई का संकेत देते राहुल

पिछले माह यानी मार्च में, तत्पश्चात मात्र 6 दिन पहले कांग्रेस की अहमदाबाद में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आये ही थे, मंगलवार-बुधवार को वे फिर से गुजरात में थे। वे आये थे एक ऐसे राज्य की पार्टी इकाई में प्राण फूंकने पहुंचे जो पिछले साढ़े तीन दशकों से सत्ता से बाहर है। यहां पार्टी का केवल एक सांसद है तथा सिर्फ 17 विधायक हैं। दरअसल कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ-साथ राहुल गांधी जमीनी स्तर तक पार्टी का रूप-रंग बदलते दिखाई दे रहे हैं। राज्य के चुनाव अभी दूर हैं (2027 में होंगे) लेकिन संगठन की जो नयी कार्यप्रणाली यहां राहुल विकसित कर रहे हैं, वह अन्य सूबों में भी लागू हो सकती है। होनी ही चाहिये। पिछले दौरे पर राहुल ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मैराथन मुलाकातें की थीं। उसके बाद कार्यकर्ताओं को दिये स बोधन में उन्होंने भितरघात करने वाले कांग्रेसियों को साफ कर दिया था कि %वे भारतीय जनता पार्टी की बी-टीम बनकर काम करने की बजाय संगठन से बाहर चले जायें।% इस बात को उन्होंने इस दौरे में दोहराया है। उन्होंने पिछली बार गुजरात में ही कहा था कि पार्टी से कुछ ऐसे लोगों को निकाल बाहर करने की जरूरत है जो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं।% साफ है कि उनकी यह चेतावनी गुजरात के नेताओं तक सीमित न होकर सभी राज्य इकाइयों के लिये अलार्म होगी।मंगलवार को अहमदाबाद कांग्रेस कार्यालय में उन्होंने जिला अध्यक्षों तथा पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की थी जिसमें 5 सदस्यों की एक टीम बनाई गई जो 45 दिनों में आलाकमान को जमीनी रिपोर्ट देगी। इसके बाद नये जिलाध्यक्ष नियुक्त होंगे। इसका मानदण्ड उनकी सक्रियता, पार्टी के प्रति निष्ठा एवं दृढ़ वैचारिक प्रतिबद्धता होगी। बुधवार को राहुल ने मोडासा जिले के अरावल्ली में %संगठन सृजन अभियान% की शुरुआत की जिसका उद्देश्य जिला कांग्रेस समितियों और उनके अध्यक्षों को सशक्त और जवाबदेह बनाना है। इस नई प्रणाली से पार्टी के संगठन को मजबूती मिलने की आशा है। याद हो कि अहमदाबाद सीडब्ल्यूसी में राहुल ने कहा था कि जिला अध्यक्ष ही संगठन की नींव बनें। वे ही पार्टी की मु य ताकत होने चाहिये। जिला कमेटी और जिला अध्यक्ष को शीर्ष नेतृत्व पार्टी की बुनियाद बना रहा है। पार्टी इकाई ने अधिवेशन के बाद गुजरात के 33 जिलों और 8 प्रमुख शहरों के अध्यक्षों की नियुक्ति हेतु 42 केंद्रीय और 183 प्रदेश स्तर के पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। उन्होंने इस बात को दोहराया कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हराने की ताकत केवल कांग्रेस में है; और जीत का रास्ता गुजरात से होकर जाता है। बुधवार की बैठक में राहुल ने कहा कि, %देश में चल रही लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं वरन भाजपा-संघ और कांग्रेस के बीच विचारधाराओं की लड़ाई भी है। उन्होंने याद दिलाया कि %गुजरात ने ही पार्टी को दो सबसे बड़े नेता- महात्मा गांधी और सरदार पटेल दिए हैं परन्तु हमें लंबे समय से गुजरात में नाकामी मिल रही है।% राहुल का यह बतलाना कि कई सूत्रों से उन्हें जानकारी मिली है कि वरिष्ठ नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा रचनात्मक नहीं बल्कि विनाशकारी है। साथ ही, टिकट वितरण प्रक्रिया में स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं को शामिल न किया जाना भी नुकसानदेह साबित हुआ है।गुजरात के तीनों ही दौरे (अधिवेशन समेत) पार्टी को अनेक महत्वपूर्ण संकेत व संदेश दे रहे हैं। हर बार राहुल का यह कहना कि भाजपा को हराने की ताकत कांग्रेस रखती है, न सिर्फ कार्यकर्ताओं में जोश भर रहा है वरन उन्हें 2027 की तैयारियां अभी से करने के लिये प्रेरित भी करता है। यह केवल गुजरात की बात नहीं वरन लगभग हर राज्य में यही दिखता है कि चुनाव सिर पर आने तक कांग्रेस की तैयारियां नहीं रहतीं। अंतिम समय तक उ मीदवार घोषित नहीं होते तथा जिसे भी प्रत्याशी बनाकर उतारा जाता है, प्रतिस्पर्धी खेमा जो पार्टी टिकट से वंचित रह जाता है वह या तो निष्क्रिय हो जाता है अथवा भाजपा को प्रत्यक्ष-परोक्ष मदद करता है। यदि कोई समझे कि राहुल की यह चेतावनी केवल गुजरात इकाई के लिये है तो वह गलतफहमी में है।

संघवाद की हिमायत में फैसला

राजेंद्र शर्मा

इस फैसले का असर यह भी है कि केरल की एलडीएफ सरकार ने भी ऐसे ही मामले में, अपने राज्य के राज्यपाल द्वारा लंबे अर्से से रोक कर रखे गए, विधानसभा द्वारा पारित हुए विधेयकों को, इसी प्रकार से पारित घोषित किए जाने की मांग की है। राज्यपालों की विधानसभा की कार्यवाही में रोड़े अटकाने की अनुचित हरकतों को कटघरे में खड़ा किए जाने की यह बात निकली है, तो दूर तक जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले में स्पष्ट शब्दों में और बलपूर्वक इस बात को कहा गया है कि राज्यपाल की भूमिका तो संविधान के रखवाले की है यानी उसका काम संघीय व्यवस्था का सुचारु रूप से काम करना सुनिश्चित करने में मदद करना है। उसकी भूमिका किसी भी तरह से राजनीतिक खिलाड़ी की नहीं है और विपक्षी राजनीतिक खिलाड़ी की तो हर्गिज-हर्गिज नहीं है।

नरेंद्र मोदी के राज में राज्यपाल के पद को जिस तरह से विपक्ष-शासित राज्यों में सत्ताधारी संघ-भाजपा जोड़ी की क्षुद्र राजनीति का हथियार बनाया गया है, उस पर यकायक किसी तरह से रोक लग जाएगी, यह मानना मुश्किल है। फिर भी तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु राज्यपाल आदि मामले में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने जो असाधारण फैसला सुनाया है, उसने मौजूदा निजाम में राज्यपालों की भूमिका के सवाल को एक बार फिर बहस के केंद्र में ला दिया है।न्यायाधीशगण जेबी पारदीवाला और आर माधवन के फैसले का महत्व सिर्फ इतना ही नहीं है कि पहली बार तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित ऐसे दस विधेयकों को राज्यपाल की मंजूरी के बिना ही पारित करार दे दिया गया है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अनुसार राज्य के राज्यपाल ने %अवैध% तरीके से सालों से रोका हुआ था।

राज्यपाल की यह नकारात्मक सक्रियता इस हद तक पहुंच गयी थी कि 2023 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इसी विवाद में यह फैसला दिया था कि राज्यपाल, विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को अनिश्चित काल तक अपने पास रोक कर नहीं रख सकता है और उसके पास ऐसे किसी भी विधेयक को मंजूरी देने के सिवा दो ही विकल्प थे, या तो विधेयक को नामंजूर कर के विधानसभा को लौटा दे या फिर परामर्श के लिए राष्ट्रपति को भेज दे। उस समय राज्यपाल ने बरसों से रोक कर रखे जा रहे विधेयकों को विधानसभा के दोबारा पारित कर के भेजने के बाद, उन पर मंजूरी देने के बजाए, कथित रूप से परामर्श के नाम पर राष्ट्रपति के पाले में डाल दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस समूचे धतकर्म को अवैध करार देते हुए, संबंधित दस विधायकों को राज्य विधानसभा द्वारा उनके दोबारा पारित कर लौटाए जाने की तारीख से ही, पारित घोषित कर दिया है।

इस फैसले का असर यह भी है कि केरल की एलडीएफ सरकार ने भी ऐसे ही मामले में, अपने राज्य के राज्यपाल द्वारा लंबे अर्से से रोक कर रखे गए, विधानसभा द्वारा पारित हुए विधेयकों को, इसी प्रकार से पारित घोषित किए जाने की मांग की है। राज्यपालों की विधानसभा की कार्यवाही में रोड़े अटकाने की अनुचित हरकतों को कटघरे में खड़ा किए जाने की यह बात निकली है, तो दूर तक जाएगी। याद रहे कि उत्तर हो या दक्षिण या पूर्व, कोई भी विपक्ष-शासित राज्य नहीं है, जहां मोदी राज द्वारा बैठाए गए राज्यपालों ने इस तरह की असंवैधानिकता नहीं की है। तमिलनाडु और केरल ही नहीं, तेलंगाना, पंजाब, दिल्ली आदि की सरकारें भी, ऐसी ही शिकायतों के साथ सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंची थीं। इसे देखते हुए यह कहने में जरा भी अतिरंजना नहीं होगी कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला, राज्यपालों के ऐसी असंवैधानिकता करने के लिए जि मेदार, केंद्र सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा है। लेकिन, जैसे इस मामले में मोदी राज की इसी संलिप्तता का परोक्ष साक्ष्य पेश करते हुए, तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी हरकतों को गैर-कानूनी ठहराते हुए सुप्रीम भर्त्सना किए जाने के बावजूद, न सिर्फ राज्यपाल के पद से इस्तीफा देने से इंकार कर दिया है, वह तो राज्यपाल के पद की मर्यादाओं को मिट्टी में मिलाते हुए, हर रोज नये-नये विवाद खड़े करने में लगा हुआ है। ताजातरीन विवाद उसने मदुरै में एक सार्वजनिक शिक्षा संस्था के कार्यक्रम में छात्रों से %%जय श्रीराम%% के नारे लगवा कर किया है, जो एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए सरासर असंवैधानिक आचरण है। बहरहाल, इन मामलों में केंद्र की संलिप्तता के प्रत्यक्ष साक्ष्य भी कम नहीं हैं। ऐसे ही एक साक्ष्य में केंद्र की ओर से इसके इशारे किए जा रहे हैं कि सरकार, सुप्रीम कोर्ट के उक्त फैसले के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर करने जा रही है। वास्तव में इस मामले में केंद्र सरकार को ही एक प्रकार से एक पक्ष बनाते हुए, देश के एडवोकेट जनरल ने इस मामले में तमिलनाडु के राज्यपाल की पैरवी की थी। तमिलनाडु के राज्यपाल के पक्ष में एडवोकेट जनरल द्वारा यह पूरी तरह से संविधानविरोधी और संघीय व्यवस्था विरोधी दलील दी गयी थी कि राज्यपाल के पास, विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूर करने, नामंजूर करने या राष्ट्रपति को भेजने के सिवा एक चौथा विकल्प भी होता है, जिसे आम लोगों की भाषा में पॉकेट वीटो कहा जाता है यानी विधेयक को लिया और जेब में डालकर भूल गए। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले में न सिर्फ यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्यपाल को इस तरह के किसी भी वीटो का कोई अधिकार नहीं है, बल्कि यह भी साफ कर दिया गया है कि राज्यपाल को और यहां तक कि राष्ट्रपति को भी, ऐसे विधेयकों के मामले में इस समुचित समय सीमा के अंदर अपना फैसला देना होगा और यह समय सीमा एक महीने से लेकर तीन महीने तक की है। इस तरह, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से तो राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा के निर्णय के रूप में, राज्य की जनता की इच्छा का रास्ता रोके जाने की इस बढ़ती प्रवृत्ति का रास्ता बंद ही कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले में स्पष्ट शब्दों में और बलपूर्वक इस बात को कहा गया है कि राज्यपाल की भूमिका तो संविधान के रखवाले की है यानी उसका काम संघीय व्यवस्था का सुचारु रूप से काम करना सुनिश्चित करने में मदद करना है। उसकी भूमिका किसी भी तरह से राजनीतिक खिलाड़ी की नहीं है और विपक्षी राजनीतिक खिलाड़ी की तो हर्गिज-हर्गिज नहीं है। कहने की जरूरत नहीं है कि मोदी राज में विपक्ष शासित राज्यों के राज्यपालों को, विपक्षी राजनीतिक खिलाड़ी की ठीक ऐसी ही भूमिका में घटा दिया गया है। अव्वल तो राज्यपालों की नियुक्ति ही इन अपेक्षाओं के आधार पर ही की जा रही है और अगर कोई कमी रह जाती है, तो केंद्र के निर्देशों से उन्हें संघ-निर्देशित रास्ते पर ले आया जाता है। बेशक, हमारे देश में संघीय व्यवस्था के संदर्भ में, राज्यपालों के पद का केंद्र की राजनीतिक इच्छा के हिसाब से दुरुपयोग किए जाने का इतिहास, मोदी राज से कहीं पुराना है। तरह-तरह के बहानों से निर्वाचित राज्य सरकारों को गिराने/हटाने के लिए राज्यपाल के पद का इतनी बार दुरुपयोग हुआ है कि न सिर्फ इस पद की भूमिका पर कई आयोगों/कमेटियों द्वारा रोक-टोक करने वाली टिप्पणियां की गयी हैं तथा शर्तें लगायी गयी हैं, वास्तव में अनेक हलकों से इस पद की ही जरूरत पर भी सवाल उठते रहे हैं। इसके बावजूद, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है कि मोदी राज में इन प्रवृत्तियों को एक नयी ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया गया है और राज्यपालों को विपक्षी सरकार के खिलाफ इस हद तक तथा इतनी नंगई से सत्ताधारी पार्टी के सक्रिय एजेंटों में तब्दील किया गया है, जैसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था।

इस खेल की नंगई को समझने के लिए एक तथ्य की ओर ध्यान दिलाना ही काफी होगा। तमिलनाडु विधानसभा के जिन विधेयकों को राज्यपाल रवि ने अनंतकाल तक रोके रखने की कोशिश की थी और जिन्हें अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कानून बना दिया गया गया है, उनमें उच्च शिक्षा क्षेत्र से संबंधित विधेयक भी शामिल हैं, जो राज्य विश्वविद्यालयों के चांसलर का पद राज्यपाल से लेकर, निर्वाचित सरकार को सौंपने का प्रयास करते हैं। मोदी राज में संघ-भाजपा द्वारा राज्यपालों को माध्यम बनाकर, जिस तरह राज्य विश्वविद्यालयों पर ही कब्जा करने का अभियान छेड़ा गया है, उसके सामने तमिलनाडु ही नहीं केरल, पश्चिम बंगाल आदि अन्य अनेक विपक्ष-शासित राज्यों को भी, राज्यपाल को पदेन चांसलर के पद से हटाने का रास्ता अपनाना पड़ा है। लेकिन, मोदी राज द्वारा बैठाए गए राज्यपाल, इसके सीधे उनके अपने हितों से जुड़ा मामला होने के बावजूद, विधानसभाओं द्वारा पारित इन विधेयकों को भी दबा कर बैठे रहे हैं। बेशक, विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों का रोक कर रखा जाना, विपक्षी सरकारों के खिलाफ राज्यपाल के पद के दुरुपयोग का एकमात्र हथियार नहीं है। लेकिन, यह संघीय व्यवस्था की जड़ पर ही प्रहार करने वाला ऐसा अतिवादी हथियार जरूर है, जिसकी असंवैधानिकता सुप्रीम कोर्ट की छन्नी से बचकर नहीं निकल पायी है। इससे मौजूदा शासन की बढ़ती संघवादविरोधी प्रवृत्ति पर कुछ अंकुश लगने की उ मीद तो की ही जा सकती है। पर यह अंकुश उसी हद तक काम करेगा, जिस हद तक विपक्षी ताकतें सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के संघवाद तथा जनतंत्र के लिए महत्व को, आम जनता के बीच ले जाने में कामयाब होंगी।

राजनैतिक स्वतंत्रता के साथ सामाजिक स्वतंत्रता के पक्षधर थे डॉ. भीमराव अंबेडकर

गणेश कछवाहा

नेतागण जिस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं वो मालिकों का जनतंत्र है। वे जिस तथाकथित लोकशाही की बार-बार दुहाई दे रहे हैं वो मालिकों की लोकशाही है। इसके विपरीत भीमराव अंबेडकर का मानना था जब तक पूंजीवाद कायम है तब तक सही मायनों में न स्वतंत्रता संभव है और न समानता। वास्तव अर्थ में समानता हासिल करने के लिए पूंजीवादी व्यवस्था को बदलना होगा उसके बाद ही वास्तविक अर्थ में समानता प्राप्त की जा सकती है। दलित सामाजिक संघर्षों के प्रणेता,भारतीय संविधान के निर्माता और लोकतंत्र के प्रबल समर्थक डॉ. बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्रता की वकालत तो की, लेकिन उनका मतलब केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी, बल्कि सामाजिक स्वतंत्रता एक प्रमुख लक्ष्य था। स्वतंत्रता के प्रति उनका दृष्टिकोण व्यापक था।

उनका मानना था कि %राष्ट्रीय स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सामाजिक स्वतंत्रता के बीच बहुत बड़ा अंतर है। इसे समझे बिना हम सही और पूरी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते थे। भारत को अगर एक विदेशी देश की गुलामी से मुक्त किया जाए तो उसे राजनीतिक स्वतंत्रता मिलती है, लेकिन फिर भी स्वतंत्र भारत के लोग स्वतंत्र नहीं होते हैं। क्योंकि विदेशी शासकों के जाने पर राजनीतिक दासता समाप्त तो हो जाती है,परंतु उनके जाने के बाद भी उस देश के लोगों की दासता जारी रहती है, उन्हें सामाजिक स्वतंत्रता नहीं मिलती है। तो इसे हम पूरी आज़ादी या स्वतंत्रता कैसे कह सकते हैं।%

- डॉ. बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर

समान अवसरों और अधिकारों से अनेकों वर्षों से वंचित रहे बहिष्कृत अछूत समाज को जब तक गुलामी के जंजीरों से मुक्त नहीं किया जाता, उनकी दासता को मिटाने में जब तक स्थापित शासन को सफलता नहीं मिलती तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता केवल मुठ्ठी भर लोगों के हितों की रक्षा करेगी, और ऐसी स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है।

बाबा साहेब ने महसूस किया कि सदियों से समान अवसरों और अधिकारों से वंचित रखे गए बड़े वर्ग के लिए केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने से लाभ नहीं होगा, वे राष्ट्रीय स्थापित मानकों विचारधाराओं के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएंगे।

डॉ. बाबा साहब अंबेडकर का सामाजिक दर्शन तीन शब्दों - स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित है। बाबा साहेब समानता के सबसे बड़े समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने जीवन भर समानता के लिए कड़ा संघर्ष किया।

सन् 1943 में इंडियन फेडरेशन के कार्यकर्ताओं के एक शिविर में भाषण देते हुए अंबेडकर ने कहा -

%हर देश में संसदीय लोकतंत्र के प्रति बहुत असंतोष है। भारत में इस प्रश्न पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। भारत संसदीय लोकतंत्र प्राप्त करने के लिए बातचीत कर रहा है। लेकिन हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। यह उतना बढ़िया उत्पाद नहीं है जितना दिखाई देता है।

इसी भाषण में आगे कहा कि - संसदीय लोकतंत्र कभी जनता की सरकार नहीं रही,न जनता के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार रही। कभी ऐसी भी सरकार नहीं रही जो जनता के लिए हो।

भीमराब अंबेडकर ने 1942 के रेडियो भाषण में स्वाधीनता, समानता और भाईचारा, इन तीन सूत्रों का उद्भव फ्रांसीसी क्रांति में देखा। उन्होंने कहा %मजदूर के लिए स्वाधीनता का अर्थ है जनता के द्वारा शासन। संसदीय लोकतंत्र का अर्थ जनता के द्वारा शासन नहीं है।अंबेडकर ने संसदीय लोकतंत्र की व्या या करते हुए लिखा-%संसदीय लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें जनता का काम अपने मालिकों के लिए वोट देना और उन्हें हुकूमत करने के लिए छोड़ देना होता है।% अंबेडकर ने लोकतंत्र को मजदूरवर्ग के नजरिए से देखा और उस पर अमल करने पर भी जोर दिया।

नेतागण जिस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं वो मालिकों का जनतंत्र है। वे जिस तथाकथित लोकशाही की बार-बार दुहाई दे रहे हैं वो मालिकों की लोकशाही है। इसके विपरीत भीमराव अंबेडकर का मानना था जब तक पूंजीवाद कायम है तब तक सही मायनों में न स्वतंत्रता संभव है और न समानता। वास्तव अर्थ में समानता हासिल करने के लिए पूंजीवादी व्यवस्था को बदलना होगा उसके बाद ही वास्तविक अर्थ में समानता प्राप्त की जा सकती है। इसके विपरीत नेतागण पूंजीवाद को बनाए रखकर ही नियमों में सुधार की बात कर रहे हैं।

अंबेडकर की नजर में वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ है सभी किस्म के विशेषाधिकारों का खात्मा। नागरिक सेवाओं से लेकर फौज तक,व्यापार से लेकर उद्योग धंधों तक सभी किस्म के विशेषाधिकारों को खत्म किया जाए। वे सारी चीजें खत्म की जाएं जिनसे असमानता पैदा होती है।

अंबेडकर की धारणा थी कि - लोकप्रिय हुकूमत के तामझाम के बावजूद संसदीय लोकतंत्र वास्तव में आनुवंशिक शासकवर्ग द्वारा आनुवंशिक प्रजा वर्ग पर हुकूमत है। यह स्थिति वर्णव्यवस्था से बहुत कुछ मिलती जुलती है। ऊपर से लगता है कोई भी आदमी चुना जा सकता है, मंत्री हो सकता है, शासन कर सकता है। वास्तव में शासक वर्ग एक तरह वर्ण बन जाता है। उसी में से,थोड़े से उलटफेर के साथ,शासक चुने जाते हैं। जो प्रजा वर्ग है, वह सदा शासित बना रहता है।% (संदर्भ- जगदीश्वर चतुर्वेदी, कोलकाता विश्वविद्यालय के अवकाश प्राप्त प्रोफेसर व जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष हैं।)

डॉ. अंबेडकर सामाजिक समानता केलिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने गणितीय समानता या कृत्रिम समानता को स्वीकार नहीं किया। प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं और क्षमताओं में एक स्वाभाविक भिन्नता होती है। बाबा साहब अंबेडकर का मानना था कि वंश, धर्म, जाति तथा सामाजिक स्थान ऐसे आधार पर भेदभाव करना समाजवादी व्यवस्था के साथ धोखा होगा।डॉ भीमराव अंबेडकर को हमें आधुनिक मिथभंजक के रूप में देखना चाहिए। भारत और लोकतंत्र के बारे में परंपरावादियों, सनातनियों, डेमोक्रेट, ब्रिटिश बुद्धिजीवियों और शासकों आदि ने अनेक मिथों का प्रचार किया है। ये मिथ आज भी आम जनता में अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। बाबा साहेब ने भारतीय समाज का अध्ययन करते हुए उसके बारे में एक नयी सोच पैदा की है। भारतीय समाज के अनेक विवादास्पद पहलुओं का आलोचनात्मक और मौलिक विवेचन किया है। भारत में भक्त होना आसान है समझदार होना मुश्किल है। बाबा साहेब ऐसे विचारक हैं जो शूद्रों के सामाजिक ताने-बाने को पूरी जटिलता के साथ उद्घाटित करते हैं। बाबा साहेब के भी भक्तों में एक बड़ा तबका है जो दलित चेतना और दलित विचारधारा से लैस हैं। उन्हें भक्तों के आभा मंडल से बाहर निकलकर निश्चिंतता, चेतना स पन्न और डॉ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारधारा से लैस होकर सामाजिक स्वतंत्रता, समानता, उत्थान, राजनैतिक और संविधानिक अधिकारों की रक्षा के संघर्षों को आगे बढ़ाना ही डॉ बाबा साहब के सपनों को साकार करना होगा। बाबा साहेब का मानना था कि - %वह मनुष्य को मात्र मनुष्य नहीं रहने देती और आज़ाद भी नहीं। मनुष्य पूर्ण मनुष्य तभी बन सकता है जब वह अन्य से यह कहें कि समस्त प्राणी से बिना किसी स्वार्थ के पवित्र आत्मीय और प्रेम का रिश्ता बनाए।

विविध समाचार

राज्य में अवैध परिवहन किए जा रहे 19 हजार 320 क्विंटल धान जब्त

रायपुर २६/११ (संवाददाता): छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ होने के पूर्व से ही प्रदेश में अवैध परिवहन से आने वाले धान की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पिछले एक नवंबर से 16 नवंबर तक लगभग 19 हजार 320 क्विंटल धान जब्त किया गया है। इस बार मार्कफेड द्वारा राज्य में अवैध परिवहन के जरिए अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ आने वाले धान को रोकने के लिए राज्य के सीमावर्ती जिलों में चेकपोस्ट और कलेक्टर की अध्यक्षता में टॉस्कफोर्स भी बनाए गए हैं। इसके साथ ही मार्कफेड में स्थापित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था की सतत् निगरानी की जा रही है। मार्कफेड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले एक नवंबर से 16 नवंबर के अवधि में सीमावर्ती विभिन्न जिलों से छत्तीसगढ़ राज्य में अवैध परिवहन के माध्यम से आने वाले धान में सर्वाधिक महासमुंद जिले में 4266 क्विंटल धान जब्त किया गया है। इसी प्रकार बलरामपुर जिले में 4139 क्विंटल, सूरजपुर जिले में 1750 क्विंटल, रायगढ़ जिले में 1201 क्विंटल, जशपुर जिले में 1157 क्विंटल, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में 967 क्विंटल, कोण्डागांव जिले में 869 क्विंटल, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 687 क्विंटल, राजनांदगांव 607 क्विंटल, मुंगेली में 490 क्विंटल, बलौदाबाजार में 386 क्विंटल, बिलासपुर में 273 क्विंटल, कोरिया में 253 क्विंटल, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 250 क्विंटल, सरगुजा में 240 क्विंटल, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 228 क्विंटल, दंतेवाड़ा में 220 क्विंटल, बस्तर जिले में 218 क्विंटल, सक्ती में 137 क्विंटल, सुकमा में 130 क्विंटल, बालोद में 123 क्विंटल, गरियाबंद में 122 क्विंटल, जांजगीर-चांपा में 119 क्विंटल, कवर्धा में 90 क्विंटल, कोरबा में 85 क्विंटल, रायपुर में 84 क्विंटल, धमतरी में 72 क्विंटल, नारायणपुर में 53 क्विंटल, दुर्ग में 38 क्विंटल, बेमेतरा में 32 क्विंटल, मोहला-मानपुर-चौकी में 27 क्विंटल धान जब्त किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के पूर्व प्रदेश में अवैध धान परिवहन और संग्रहण पर सख्त निगरानी जारी रखते हुए आज दो महत्वपूर्ण कार्रवाईयाँ की गईं। मार्कफेड के इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम से प्राप्त 600 बैग (231.5 क्विंटल) अवैध धान संबंधी अलर्ट पर तत्काल कार्रवाई करते हुए कोंडागांव जिले की टीम ने मौके पर पहुंचकर धान जप्त किया। सीमावर्ती जिलों में निगरानी बढ़ाए जाने और त्वरित अलर्ट-रिस्पॉन्स सिस्टम की बदौलत अन्य राज्यों से धान की अवैध आमद को रोकने में प्रभावी सफलता मिल रही है। इसी क्रम में, रात्री गश्त के दौरान ग्राम त्रिशूली, थाना सनवाल क्षेत्र में अशोक सिंह पिता रामचरित्र के घर के बाहर बने शेड में दो अलग-अलग स्थानों पर कुल 222 कट्टा धान पाया गया। विवाद की स्थिति को देखते हुए दिन में पुनः तहसीलदार रामचंद्रपुरपुर, थाना प्रभारी सनवाल, महिला पुलिस, तथा मंडी कर्मचारियों की मौजूदगी में विस्तृत जांच की गई और धान की विधिवत जप्ती की कार्रवाई पूरी की गई।

विश्वसनीयता मीडिया की सबसे बड़ी ताकत

० जनसंपर्क विभाग द्वारा राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर विचार गोष्ठी का आयोजन

रायपुर २६/११ (संवाददाता):राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर आज जनसंपर्क संचालनालय में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस विचार गोष्ठी में संपादकों, वरिष्ठ पत्रकारों और जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। वरिष्ठ संपादक जयप्रकाश मिश्रा ने कहा कि कुछ लोग अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए भ्रामक सूचनाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ एक ही तरह की भ्रामक सामग्री को भेजते हैं, जिससे उसका एल्गोरिदम बढ़ जाता है और पाठक भ्रमित होकर उसे सच मान बैठता है। उन्होंने दिल्ली मेट्रो का उदाहरण देते हुए कहा कि श्रीधरन जी जब भी मेट्रो में किसी तरह की रूकावट आती थी तब तुरंत ही सूचना प्रचार माध्यमों में समाचार जारी कर तकनीकी त्रुटि को ठीक करने में लगने वाला संभावित समय भी बता देते थे। जब सही और गुणवत्तापूर्ण सूचनाएं आगे बढ़ती हैं तो भ्रामक सूचनाएं ठहर नहीं पाती। वरिष्ठ संपादक रवि भोई ने कहा कि खबरों की सच्चाई अहम है इससे समझौता नहीं करना चाहिए। भले ही समय लगता हो लेकिन पुष्टि के पश्चात ही खबरे प्रसारित करना चाहिए। संपादक एएन द्विवेदी ने कहा कि सूचनाओं की गुणवत्ता और उनके प्रसारण से पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर बेहद गंभीरता बरतते हुए इन्हें जनसामान्य को प्रेषित किया जाना चाहिए। इसमें छोटी चूक भी बड़ी दुर्घटना का रूप ले लेती है। वरिष्ठ पत्रकार अशोक साहू ने कहा कि पत्रकारिता में विश्वसनीयता के मानदंडों पर यदि काम किया जाए तो किसी तरह की भ्रामक सूचना जाने की आशंका नहीं रहती। अपर संचालक उमेश मिश्रा ने कहा कि मीडिया की विश्वसनीयता लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, इसे किसी भी कीमत पर बनाए रखना जरूरी है। मीडिया को तकनीकी बदलाव के चलते तेजी से फैलती गलत सूचनाओं पर अपनी जिम्मेदारी के साथ-साथ सतर्कता बरतनी होगी। अपर संचालक आलोक देव ने कहा कि मीडिया की सबसे बड़ी ताकत है उसकी विश्वसनीयता। मीडिया सिर्फ खबरे नहीं देता, प्रेस मार्गदर्शन करता है, संदेह दूर करता है और विश्वास का निर्माण करता है। उप संचालक सौरभ शर्मा ने कहा कि आज का दौर एआई का है ऐसे समय में गलत सूचनाओं का एल्गोरिथम बढ़ने से व्यापक रूप से हमारे बीच पहुंचता है। हमें ऐसी सूचनाओं को जांच-परख कर ही प्रसारित करना चाहिए। कार्यक्रम में अरविन्द मिश्रा सहित अनेक लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनसंपर्क विभाग के अधिकारी और मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित थे।

आज का राशिफल

मेष - आज के दिन धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्तियाँ विशेष रहेंगी। मन में द्विधा रहने से ठोस निर्णय नहीं ले सकेंगे। पैसे की लेन-देन या आर्थिक व्यवहार न करने की गणेशजी की सलाह है।

वृषभ - गणेशजी कहते हैं कि व्यापार में वृद्धि होने के साथ व्यापार के सम्बंध में सौदे लाभदायक साबित होंगे। आय के साधनों में वृद्धि होगी। बुजुर्गों तथा मित्र मंडल से लाभ और सुखद क्षणों का अनुभव मिलेगा।

मिथुन - शारीरिक और मानसिक सुख बने रहेंगे। नौकरी - व्यवसाय में आपके परिश्रम का मुआवजा मिलता हुआ प्रतीत होगा। अधिकारी वर्ग के प्रोत्साहन से आपका उत्साह बढ़ेगा। सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

कर्क - गणेशजी कहते हैं कि आज आपकी भाग्य वृद्धि के साथ आकस्मिक धन लाभ होगा। विदेश जाने के इच्छुक लोगों के प्रयास सफल होंगे। तथा विदेश से अच्छे समाचार आएँगे।

सिंह - आज आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना रहेगा। तबीयत के पीछे धन खर्च होने की संभावना है। निषेधात्मक विचार आपको गलत मार्ग पर न ले जाए, उसका ध्यान रखने के लिए गणेशजी कहते हैं।

कन्या - गणेशजी की कृपा से दांपत्यजीवन के सुखद क्षणों का अनुभव करेंगे। सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्र में आप ख्याति और प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। मनोरंजन की प्रवृत्तियों में भाग लेंगे। वस्त्राभूषण और वाहन की खरीदी होगी।

तुला - गणेशजी कहते हैं कि सामान्य रूप से आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और बीमार व्यक्ति के भी तबीयत में सुधार होगा। घर में सुख- शांति के वातावरण में आप समय व्यतीत करेंगे। कार्य में सफलता और यश मिलने से उत्साह बढ़ेगा।

वृश्चिक - आज यात्रा प्रवास का आयोजन न करने की सलाह गणेशजी देते हैं। स्वास्थ्य के सम्बंध में चिंतित रहेंगे। संतानों के सम्बंध में समस्याएँ खड़ी होंगी। स्वाभिमान भंग न हो इसका ध्यान रखें।

धनु - गणेशजी कहते हैं कि आज आपको अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण और घरेलू मामलों को लेकर मानसिक तनाव खड़े होने की संभावना है। मन में उठनेवाली द्विधाओं से आप मानसिक उचाट अनुभव करेंगे।

मकर - आज आप रणनीति में शत्रुओं को परास्त करेंगे। नए कार्यों के आरंभ के लिए तैयार रहें। सफलता मिलेगी। आप हरेक कार्य तन-मन से स्वस्थ रहकर करेंगे। व्यापार-धंधे में लाभ होगा।

कुंभ - गणेशजी बताते हैं कि मन में द्विधाएँ खड़ी होने से आप कोई ठोस निर्णय पर नहीं पहुँच सकेंगे। महत्वपूर्ण निर्णय न लें। वाणी पर संयम नहीं रहनेसे पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाव होने की संभावना है।

मीन - आनंद- उत्साह और तन-मन की प्रसन्नता आपके दिन में चेतना और स्फूर्ति का संचार करेंगे। नए कार्य हाथ में लेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। धार्मिक मांगलिक प्रसंगों में जाएँगे।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग ने की अपील किसान भाई रहें सतर्क

० धान खरीदी केंद्रों में पोस्टर लगाकर की जा रही जागरूकता

दुर्ग २६/११ (संवाददाता): धान खरीदी सीजन में किसानों की आर्थिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए दुर्ग पुलिस द्वारा व्यापक जागरूकता पोस्टर जारी किया गया है। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि इस संदेश को अधिक से अधिक किसानों तक पहुँचाकर सहयोग प्रदान करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धान खरीदी सीजन में किसान भाई सतर्क रहें। धान खरीदी का सीज़न शुरु हो गया है और इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के खातों में पूरे साल की मेहनत का पैसा आता है। इसी दौरान उठाई गिरोह और साइबर अपराधी सबसे अधिक सक्रिय हो जाते हैं। दुर्ग पुलिस आप सभी किसानों से अपील करती है कि पैसे की सुरक्षा के लिए सतर्क रहें, अनजान लोगों से दूरी बनाए रखें, और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें। 1. बैंक में सिर्फ अधिकृत कर्मचारी से ही मदद लें पैसे जमा या निकासी करते समय अपनी जानकारी किसी को न बताएँ। मदद चाहिए तो केवल बैंक के कर्मचारी से ही लें। बैंक में मौजूद अनजान लोग मदद के बहाने धोखा धोखा दे सकते हैं, इसलिए उनसे दूरी बनाए रखें। 2. नोटों की गिनती सिर्फ बैंक के अंदर करें पैसे निकालने के बाद नोटों की गिनती हमेशा बैंक के अंदर ही पूरी करें। बाहर सड़क या दुकान के सामने नोट गिनना सुरक्षित नहीं है। ऐसे मौके पर उठाई गिरोह आसानी से पैसे छीन सकते हैं, इसलिए पैसा बाहर न दिखाएँ। 3. बैंक आते-जाते समय पैसों को सुरक्षित रखें, बैंक से आते या जाते समय अपने पैसों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें।

पैसा हमेशा शरीर से सटाकर रखे गए बैग में रखें ताकि कोई आसानी से हाथ न लगा सके। ऐसा करने से चोरी और लूटपाट की संभावना कम होती है। सुरक्षा को सबसे पहले रखें और हर समय सतर्क रहें। 4. बैंक जाते समय किसी भरोसेमंद व्यक्ति को साथ रखें बैंक आने या जाने के समय किसी मित्र या परिवार के सदस्य को साथ लेकर जाएँ। गाड़ी को बैंक के बाहर पार्क करते समय आसपास ध्यान रखें और देखें कि कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं है। यदि आपको आसपास किसी पर संदेह हो, तो तुरंत कंट्रोल रूम 9479192099 या 112 पर संपर्क कर सूचना दें। 5. बैंक आते-जाते समय संदेह होने पर तुरंत पुलिस को बताएं अगर बैंक से लौटते समय आपको लगे कि कोई व्यक्ति आपका पीछा कर रहा है या संदिग्ध तरीके से देख रहा है, तो सीधे घर न जाएँ। ऐसी स्थिति में नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुँचें और पुलिस की मदद लें। परिवार के सदस्य को साथ लेकर घर जाना अधिक सुरक्षित रहता है। 6. नकदी को गाड़ी की डिक्की में न रखें पैसे निकालने के बाद उन्हें गाड़ी की डिक्की में रखने से बचें, ज्योंकि डिक्की का ताला अपराधी आसानी से तोड़ लेते हैं। अपराधी भीड़ में मौका देखकर गाड़ी के आसपास घूमते हैं और तरकीब से पैसा निकाल लेते हैं। इसलिए निकली हुई राशि हमेशा साथ रखें और हर समय सावधान रहें। 7. पैसे निकालकर सीधे घर जाएँ, रास्ते में रुकें नहीं बैंक से पैसे निकालने के बाद बिना रुके सीधे अपने घर या गंतव्य स्थान पर जाएँ। रास्ते में किसी अनजान व्यक्ति की बातों में न आएँ। होटल, दुकान, चाय या खरीदारी के लिए रुकने पर चोरी की घटनाएँ अधिक होती हैं। पैसे लेकर रुकना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। 9. अपनी निजी जानकारी सुरक्षित रखें किसान भाइयों, आपकी व्यक्तिगत जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने ऋरू नंबर, आधार नंबर, पैन कार्ड, बैंक पासबुक या किसी भी दस्तावेज की जानकारी न दें। इन जानकारियों से धोखा बहुत जल्दी हो सकता है। 10. OTP और PIN किसी को न बताएं अपने बैंक कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI का पासवर्ड, PIN, OTP किसी को भी न बताएं। अपराधी बैंक कर्मचारी बनकर कॉल करते हैं और ह्र्ङ्मक्क मांगकर खाते से पैसे निकाल लेते हैं। बैंक कभी भी फोन पर OTP नहीं मांगता यह 100त्न फ्रॉड होता है। 11. अनजान लिंक पर कभी ज़्लिक न करें किसान भाइयों, किसी भी अनजान लिंक, संदेश, लॉटरी, बीमा या पुरस्कार वाले मैसेज पर विश्वास न करें। इन लिंक पर ज़्लिक करते ही आपका मोबाइल या बैंक अकाउंट हैक हो सकता है। शक होने पर तुरंत उस नंबर को ज़्लॉक करें और सावधान रहें। 12. सोशल मीडिया की फर्जी जानकारी से बचें फेसबुक, व्हाट्सऐप या किसी भी सोशल मीडिया पर आए बैंक या पैसों से जुड़े संदेशों पर तुरंत भरोसा न करें। अपराधी फर्जी लिंक या APK फ़ाइल भेजकर आपके मोबाइल और खाते से पैसे निकाल लेते हैं। किसी भी जानकारी की पुष्टि हमेशा बैंक शाखा या आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर पर ही करें। 13. KYC वाले कॉल और स्स्र से सावधान रहें KYC करने के नाम पर आने वाले कॉल या मैसेज पर बिल्कुल विश्वास न करें। KYC अपडेट का बहाना बनाकर अपराधी आपका PIN, पासवर्ड और OTP माँगते हैं। खाता बंद होने की धमकी भी देते हैं यह सब फ्रॉड होता है। KYC हमेशा बैंक शाखा में जाकर ही कराएं। 14. AI आवाज़ वाले धोखाधड़ी कॉल से बचें आजकल अपराधी आपकी आवाज़ जैसी आवाज़ बनाकर कॉल करते हैं और पैसों की मांग करते हैं। सिर्फआवाज़ से किसी पर भरोसा न करें पहले वीडियो कॉल करें, पहचान की पुष्टि करें और तभी कोई निर्णय लें। ऐसी कॉल आते ही शांत रहें और तुरंत पुलिस को सूचना दें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। 15. डिजिटल गिरज़्तारी से बचें अपराधी खुद को पुलिस/CBI का अधिकारी बताकर कहते हैं कि आपका सिम, आधार या बैंक किसी अपराध में पकड़ा गया है। ऑनलाइन पैसे जमा करवाने का दबाव बनाते हैं। याद रखें पुलिस कभी फोन पर गिरज़्तारी नहीं करती, यह पूरा धोखा है। 8. अपने बैंक विवरण और धन की बात किसी से साझा न करें अपने बैंक का लेन-देन, पैसा कब निकाला या कितना निकाला ऐसी जानकारी किसी से न बताएं। यह जानकारी फैलने पर कोई भी व्यक्ति आपका फायदा उठा सकता है। अपनी आर्थिक जानकारी गोपनीय रखना ही सुरक्षित रहने का सबसे अच्छा तरीका है। 16. फर्जी ग्राहक सेवा से बचकर रहें जागरूक किसान ही सुरक्षित किसान

राज्य के 17 जिलो के डायल 112 की सेवा शुरू की जाएगी

० 450 से ज्यादा कर्मचारियों को डायल 112 के संचालन के संबंध में किया गया प्रशिक्षित

रायपुर २६/११ (संवाददाता): डायल 112 द्वितीय फेस के क्रियान्वयन में दिनांक 14-16 नवज़्बर 2025 को पुलिस मुज़्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार, पुलिस अधीक्षक डायल 112 श्री अविनाश ठाकुर के मर्गदर्शन में सेज़्टर-03 ग्राम तेन्दुआ-02 नवा रायपुर में छज़्तीसगढ़ के 17 जिलों (बालोद, बलौदाबाजार-भाटापारा, बलरामपुर-रामानुजगंज, बेमेतरा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जशपुर, कांकेर, कोण्डागांव, कोरिया, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, मुंगेली, नारायणपुर, सुकमा, सूरजपुर, गरियाबंद) से आये ईआरयू टीम के लगभग 450 से ज्यादा आरक्षक/प्रधान आरक्षक हेतु तीन दिवसीय डायल 112 तकनीकी एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उप पुलिस अधीक्षक श्री केपीएस ध्रुर्वे तथा तकनीकी कज़्पनी C-DAC के तकनीकी विषेषज्ञ गौरव वर्मा ने ईआरयू वाहनों में स्थापित PFT (पोटेबल फिल्ड टर्मिनल) के संचालन व उपयोग के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि पुलिस-फायर-चिकित्सा से जुड़ी आकस्मिक परिस्थितियों में नागरिकों द्वारा 112 में की गई कॉल सी-4 सिविल लाईन रायपुर में प्राप्त होती हैं।

Printed, Published,Edited, & Owned by Prakash Kumar Dhal, Printed at Promodini Publication, Main road , Chhend colony , Rourkela-15 & Published at ECR-73, Chhend Colony, Rourkela-15, Editor : Prakash kumar Dhal, Email:kalingasamachar@gmail.com , Mob: 9439951525, Ph. 0661-2646999

ओडिशा समाचार

कलिंग समाचार | राउरकेला, गुरूवार 27 नवंबर 2025 | पृष्ठ-6

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 16 साल बाद ओडिशा विधानसभा में अपने पुराने चैंबर में फिर से जाएंगी

भुवनेश्वर २६/११ (संवाददाता): राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल ओडिशा विधानसभा के दौरे के दौरान अपने राजनीतिक सफर की एक खास याद को फिर से ताज़ा करेंगी, जहाँ उन्होंने कभी रूरू के तौर पर काम किया था। वह शाम 4 बजे सदन के सदस्यों को संबोधित करेंगी, यह पहली बार होगा जब भारत के कोई राष्ट्रपति ओडिशा विधानसभा में बोलेंगे। ओडिशा विधानसभा की स्पीकर सुरमा पाधी ने संवाद इंग्लिश को बताया कि अपने संबोधन के बाद, राष्ट्रपति मुर्मू कमरा नंबर 11 जाएँगी, यह वह चैंबर है जहाँ उन्होंने विधायक के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान काम किया था। राष्ट्रपति के दौरे से पहले कमरे को रेनोवेट किया गया

है। द्रौपदी मुर्मू दो बार ओडिशा असेंबली के लिए चुनी गईं मुर्मू 2000 और 2004 में रायरंगपुर सीट से दो बार ओडिशा असेंबली के लिए चुनी गईं। उन्होंने बीजद-भाजपा गठबंधन सरकार में अहम पद संभाले, मार्च 2000 से अगस्त 2002 तक कॉमर्स और ट्रांसपोर्ट राज्य मंत्री रहीं और बाद में 2004 तक फिशरीज़ और एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की हेड रहीं। मुर्मू ने आखिरी बार 2009 में चैंबर का इस्तेमाल किया था। राष्ट्रपति के दौरे के लिए सिज़्योरिटी कड़ी इस बीच, राष्ट्रपति के दौरे और महीने भर चलने वाले असेंबली सेशन के लिए पूरी राजधानी में सिज़्योरिटी कड़ी कर दी गई है। कमिश्नरेट पुलिस ने चार-लेवल का सिज़्योरिटी कवर अरेंज किया है, जिसमें असेंबली ड्यूटी के लिए 33 प्लाटून फोर्स और करीब 150 ऑफिसर तैनात किए गए हैं। एंटी-टेरर स्क्वॉड और स्पेशल टीमें भी हाउस के अंदर तैनात रहेंगी। एयरपोर्ट से राजभवन और राजभवन से असेंबली तक के खास रास्तों पर 25 और प्लाटून तैनात रहेंगी। पुलिस कमिश्नर एस देव दज़ा सिंह ने मंगलवार को कहा, हमने इंतज़ामों का रिव्यू किया और ज़रूरी बदलाव के आदेश दिए। पुलिस प्रेसिडेंट के दौरे और विंटर सेशन, दोनों के लिए पूरी तरह तैयार है। सेशन में 29 वर्किंग डेज़ होंगे और यह 31 दिसंबर तक चलेगा।

छज्जू चाष प्रशिक्षण प्रदान

राउरकेला २६/११ (संवाददाता): आरएसपी के सीएसआर विभाग द्वारा पार्श्वांचल विकास संस्थान ;आईपीडी में दो दिवसीय मशरूम की खेती का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। नुआगाँव ज़्लॉक के उर्मई और बिसरा ज़्लॉक के जोबाघाट आदर्श इस्पात ग्राम, झीरपानी पुनर्वास कॉलोनी और बिसरोली गाँव के स्वयं सहायता समूह के 20 सदस्यों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। प्रशिक्षुओं को छज्जू चाष के लिए सैद्धांतिक जानकारीए व्यावहारिक प्रदर्शन और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा होने के बाद प्रत्येक प्रशिक्षु को अपने.अपने स्थानों पर खेती करने और दूसरों को इसके लिए प्रेरित करने के लिए स्व.निर्मित छज्जू उगाने का किट बैग और छज्जू के बीज की एक बोतल दी गई।

सिंटर प्लांट-2 में अभिनव समाधान से सिंटर की गुणवज़ा और उत्पादकता में वृद्धि

राउरकेला २६/११ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) के सिंटर प्लांट-2 की उद्यमी टीम ने सिंटर की गुणवज़ा और उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक अभिनव समाधान लागू किया है। टीम ने प्रेषण श्रृंखला के च्यूट में विशेष अग्रेस्सन लाइनर सफलतापूर्वक स्थापित किए, जिसके परिणामस्वरूप ज़्लास्ट फर्नेस-1 को आपूर्ति किए जाने वाले सिंटर की गुणवज़ा में उल्लेखनीय सुधार हुआ। मौजूदा प्रणाली में, सिंटर एक कन्वेयर से दूसरे कन्वेयर में जाते समय लगातार सात ऊर्ध्वाधर गिरावटों से गुजरता है।

इन बार-बार होने वाले प्रभावों से पहले सिंटर का काफी क्षरण होता था, जिससे फाइन्स का उत्पादन बढ़ जाता था और ज़्लास्ट फर्नेस में चार्ज की जाने वाली सामग्री की प्रभावशीलता कम हो जाती थी। इस चुनौती का समाधान करने के लिए, संयंत्र ने नए उच्च-प्रभाव, घर्षण-प्रतिरोधी लाइनर पेश किए हैं। इनकी स्थापना के साथ, सिंटर क्षरण में उल्लेखनीय कमी आई है। इस पहल ने फाइन्स के उत्पादन को कम करने और संवहन के दौरान सिंटर के आकार को बेहतर बनाए रखने में योगदान दिया है।

नए लाइनर्स ने च्यूट्स में प्रवाह के गुणों को सुधारकर रखरखाव की आवश्यकता कम करते हुए परिचालन विश्वसनीयता को भी बढ़ाया है। यह पहल सिंटर हैंडलिंग प्रणाली को मजबूत बनाने और समग्र संयंत्र प्रदर्शन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है ।

सीएम माझी ने संविधान दिवस पर नागरिकों को शुभकामनाएं दीं

भुवनेश्वर २६/११ (संवाददाता): ओडिशा के मुज़्यमंत्री मोहन चरण माझी ने संविधान दिवस के मौके पर सभी नागरिकों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। अपने X हैंडल पर, उन्होंने 26 नवंबर, 1949 को भारतीय संविधान को अपनाने के दिन के महत्व पर ज़ोर दिया। माझी ने लोगों से राष्ट्र-निर्माण और देश की सेवा के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करके संविधान में निहित मूल्यों का सज़्मान करने का आग्रह किया। उन्होंने भारत माता की सेवा में खुद को समर्पित करने के लिए सामूहिक प्रयासों के

महत्व पर भी ज़ोर दिया। ष्टरू की पोस्ट में लिखा था, आज, 26 नवंबर, संविधान दिवस के मौके पर, सभी को दिल से बधाई और शुभकामनाएं। आज ही के दिन 1949 में, भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से अपनाया गया था। इस शुभ अवसर पर, आइए हम राष्ट्र-निर्माण के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करके और भारत माता की सेवा में खुद को समर्पित करके अपने संविधान के मूल्यों का सज़्मान करने का संकल्प लें।

भ्रष्टाचार को ज़हर समझें-सीएम ने सरकारी कर्मचारियों से कहा

भुवनेश्वर २६/११ (संवाददाता): ओडिशा के मुज़्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मंगलवार को कहा कि सरकारी कर्मचारियों को किसी भी तरह के करप्शन को ज़हर समझना चाहिए, जो उनके करियर के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को भी खतरे में डाल सकता है। ष्टरू माझी ने यह बात भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हुए 12वें 'निजुक्ति मेला' और ओरिएंटेशन प्रोग्राम में सरकारी पदों पर कुछ नए रिज़्रूट्स को अपॉइंटमेंट लेटर देते हुए कही। ष्टरू ने कहा, करप्शन को ज़हर समझें और जितना हो सके इससे दूर रहें। यह आपके और आपके करियर के लिए बहुत खतरनाक है। इस मौके पर 12 सरकारी डिपार्टमेंट्स में कुल 7,293 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए। माझी ने कहा, हमारी सरकार ने 17 महीनों में 37,325 लोगों को सरकारी नौकरी दी है। हमने युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था और अपना वादा निभाया।

हमारा लक्ष्य दो साल में पज़्लिक सेज़्टर में 65,000 नौकरियां देना है। नए भर्तियों में से, अधिकतम 2,365 लोगों को गृह विभाग में कांस्टेबल (1,979) और ड्राइवर (386) के रूप में नियुक्त किया गया।

मच्छरों के प्रकोप से बेहाल प्लांट साइट अंचलवासी

राउरकेला२६/११ (संवाददाता): इन दिनों राउरकेला महानगर निगम ;आरएमसीद्ध की उदासीनता का फायदा विकास कार्य करने वाले ठेकेदार उठा रहे हैं। जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ठेकेदारों की मनमानी और आरएमसी के अधिकारियों की उदासीनता का ही नतीजा है कि शहर भर में नाली नालों की साफसफाई का काम आधा.अधूरा पड़ा है।

इसका जीता जागता उदाहरण प्लांट साइट थाना के ठीक सामने विगत 6 माह पूर्व आरएमसी की ओर से निजी ठेकेदार को प्लांट साइट शिव मंदिर से लेकर थाना के आगे तक नाली निर्माण का कार्यबनाने का काम दिया गया। ठेकेदार द्वारा आधे में ही नाली का काम रोक देने और उसमें गंदगी जमा

होने से उक्त मार्ग से गुजरने वाले सैकड़ों लोग सहित आसपास के दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाली की बदबू बगल में स्थित थाना तक जाने से पुलिसकर्मी भी 24 घंटे परेशान होते हैं। इस संबंध में आरएमसी में लोगों द्वारा शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से उनमें रोष व्याप्त है। नाली में गंदगी जमा होने से इस अंचल में मच्छरों का उत्पात काफी बढ़ गया है। जिससे अंचलवासी डेंगू मलेरिया आदि बीमारी को लेकर सहमे हुए हैं।बता दें कि मच्छरों के उत्पात के कारण कुछ दिन पूर्व प्लांट साइट थाना अधिकारी सुब्रत मेहेर डेंगू का शिकार हो चुके है। इस कारण थाना के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भयभीत होने के साथ लोगों ने इस नाली का काम शीघ्र पूरा करने समेत अंचल में शीघ्र सफाई करने की मांग की है।

ऐतिहासिक उषाकोठी गुफा व प्रचीन गढ़ उपेक्षित

राउरकेला २६/११ (संवाददाता): विश्व के पुरातत्विक मानचित्र में ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले का भी प्रमुख स्थान है। यहां के ऐतिहासिक शिलालेखए गढ़ए दुर्गए गुफा की कहानी हजारों साल पुरानी है। किवदंती व कहानियों में भी इसका उल्लेख है। हेमगिरए टांगरपाली एवं लेफ्रीपाड़ा ज़्लॉक इसमें प्रमुख है। जिले में पर्यटकों को आकृष्ट करने वाले हेमगिर के जूनागढ़ए माणिकमुड़ाए लेफ्रीपाड़ा के उषाकोठीए टांगरपाली के बेलसरागढ़ का नाम सबसे ऊपर है जिसमें सुंदरगढ़ का इतिहास छिपा है।

प्राचीन शिलालेखए कलाकृति की सुरक्षा नहीं होने से यह नष्ट होने लगे हैं। इस ओर प्रशासन व पुरातत्व विभाग की भी नजर नहीं जा रही है। सुंदरगढ़ जिले में ऐतिहासिक शिलालेखए चित्र तथा कलाकृति आज भी देखने को मिलते हैं। इस पर शोध एवं अध्ययन की जरूरत है। इनकी सुरक्षा के लिए प्रशासन एवं पुरातत्व विभाग की ओर से पहल नहीं हो रही है जिससे धीरे धीरे यह नष्ट हो रहे हैं। पूर्व पाषाण युग से लेकर रामायणए महाभारत युग तथा शरब वंशीय राजा से लेकर कोशल राज्य तक का इतिहास एवं किंवदंतियां साक्षी यहां की गुफा हैं।

टांगरपाली ज़्लॉक में प्रसिद्ध ऐतिहासिक पीठ बेलसरागढ़ स्थित अखरपहाड़ एवं चुड़ापहाड़ी गुफाए लेफ्रीपाड़ा ज़्लॉक के उषाकोठी शैलाश्रयए हेमगिर स्थित ऋषिबिलए जूनागढ़ए माणिकमुड़ा गुफा समेत अन्य क्षेत्रों में शिलालेख व चित्र हजारों साल पुराने हैं। अनुसंधान के लिए यहां काफी अवसर हैं।

ये इलाके दुर्गम क्षेत्र में होने के बावजूद पर्यटक यहां आ रहे हैं। प्रशासनिक उपेक्षा के कारण आरक्षित जंगल में स्थित शिलालेखए कलाकृतियां तथा गुफा आदि पर संकट है। प्रकृति के दोहन व जंगल की कटाई के कारण भी इस पर खतरा उत्पन्न हो गया है। जिला संस्कृति एवं पर्यटन विभागए खनिज प्रतिष्ठान से भी इसे आवश्यक सुविधा नहीं मिल पा रही है।

ब्राह्मणी के बाद कोयल नदी घाट पर बालू माफिया की नजर

राउरकेला २६/११ (संवाददाता): सुदरगढ़ जिले के पानपोष अनुमंडल के पांच तहसील अंतर्गत 44 बालू घाट में से अधिकतर की लीज अवधि पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद बालू का खनन व परिवहन जारी है।

तहसील की ओर से नीलामी में देर किए जाने से माफिया व ठेकेदार घाट से बालू का अवैध रूप से उठाव कर मालामाल हो रहे हैं। तहसील अधिकारियों की ओर से नाम मात्र की छापेमारी कर जुर्माना लेकर छोड़ दिए जाने से अवैध कारोबारियों का हौसला बढ़ गया है। अब बालू माफिया की नजर ब्राह्मणीए शंख के बाद कोयल नदी घाट से बालू खनन व तस्करी पर है। राउरकेला तहसील में सातए बिसरा में सातए कुआरमुंडा में 13ए लाठीकटा में आठए बीरमित्रपुर में नौ बालू घाट हैं। राउरकेला तहसील में ब्राह्मणी नदी पर तरककेरा.1, तरकेरा.2, तरकेरा.3ए कोयल नदी में तुमकेलाए लुआकेराए प्रधानपाली व सेज़्टर.16ए कोयलनगर बालूघाट हैं। इनमें से दो की नीलामी नहीं हुई है इनके बावजूद बालू का खनन व परिवहन जारी है।इसी तरह बिसरा तहसील में जामसेरा.1ए जामसेरा.2, उडसू, कुंडापोष, जोबाघाट, बड़बंबुआए मिटकुंदरी बालू घाट हैं। इसमें से केवल दो की नीलामी हुई है। शेष की लीज अवधि खत्म हो चुकी है पर बालू का खान पहले की तरह ही जारी है। कुआरमुंडा तहसील में 13 में से बीजू बंधए पसराए जमुनानाकीए कुदाबेड़ा घाट से बालू ढुलाई की अनुमति है जबकि अन्य नौ की नीलामी होनी है। यहां से भी अवैध रूप से बालू का खनन व परिवहन जारी है। बीरमित्रपुर तहसील क्षेत्र में तेतरकेलाए गोपुरए लंकेइए जाहिरटोली घाट की नीलामी हुई है .

राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा कुआरमुंडा प्रखंड में आयोजित बहु-आयामी स्वास्थ्य शिविर से 250 से अधिक ग्रामीण लाभान्वित

राउरकेला २६/११ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) द्वारा कुआरमुंडा प्रखंड के कचारू गाँव स्थित रताखंडी राजकीय उच्च विद्यालय में एक बहु--विषयक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) विभाग द्वारा आरएसपी के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (एमएंडएचएस) विभाग के सहयोग से आयोजित किया गया था।

मुज़्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा), डॉ. जयंत कुमार आचार्य, महाप्रबंधक प्रभारी (सीएसआर), सुश्री मुनमुन मित्रा, महाप्रबंधक (सीएसआर), श्री बी मल्लिक, उप महाप्रबंधक (सीएसआर), श्री आर एस बाड़ा, उप महाप्रबंधक (सीएसआर), श्री टी बी टोप्पो, सहायक महाप्रबंधक (सीएसआर), श्री बी जेना, उप प्रबंधक (सीएसआर) श्री एस के सुकुला और आरएसपी के अन्य अधिकारियों ने शिविर का दौरा किया और ग्रामीणों से बातचीत की। मरीजों की जाँच करने वाली आरएसपी की डॉज़्टरों की टीम में डॉ. सोनिया जोशी (नेत्र रोग), डॉ. गौतम दास (ईएनटी), डॉ. मनोज कुमार प्रधान (शल्य चिकित्सा), डॉ. मनभंजन मुंड (बाल रोग), डॉ. दिव्या (ओ एंड जी), डॉ. लीजा देव (दंत चिकित्सा) और डॉ. नीलकंठ साहू (चिकित्सा) शामिल थे। उन्हें सुश्री मौसमी किशन, सुश्री भाग्यश्री, सुश्री सस्मिता ओराम, कुमारी पूर्णिमा ठाकुर और सीएसआर समन्वयक श्री बी के महापात्र द्वारा आवश्यक सहायता प्रदान की गई।

शिविर में 261 मरीजों की जाँच की गई और उन्हें मुज़्त दवाइयाँ और परामर्श प्रदान किये गए । इसके अलावा, विभिन्न सीएसआर योजनाओं के तहत इस्पात जनरल अस्पताल में आगे के इलाज के लिए 5 मरीजों की पहचान भी की गई।

उल्लेखनीय है कि, आरएसपी द्वारा पार्श्वांचल गांवों में आयोजित किए जा रहे चिकित्सा शिविर न केवल दूरदराज के गांवों में रहने वाले लोगों तक पहुंचते हैं बल्कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को आईजीएच में मुज़्त इलाज के लिए महंगी शल्यचिकित्सा भी प्रदान करते हैं।